

मुख्यमंत्री ने दौलत राम कॉलेज में शताब्दी शैक्षणिक भवन और कंप्यूटर सेंटर का किया उद्घाटन

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में शताब्दी शैक्षणिक भवन, कंप्यूटर केंद्र और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। छात्राओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बेटियों को अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। उन्हें किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में फैकल्टी रीडिंग रूम, सेमिनार रूम, पुस्तकालय में श्री रामालय, रीसाइक्लिंग यूनिट और बेकरी यूनिट का निरीक्षण कर शैक्षणिक, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने ऑडिटोरियम के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही, ‘मिस डीआरसी टैलेंट हंट’ का शुभारंभ कर छात्राओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और आत्मविश्वास के साथ मंच पर आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह, दौलत राम कॉलेज की प्राचार्या प्रो. सविता रॉय, कॉलेज की



गवर्निंग बोर्डि के अध्यक्ष मुकुल गुप्ता, विजय शंकर तिवारी सहित अन्य शिक्षकगण और छात्राएं उपस्थित रहीं। दौलत राम कॉलेज की पूर्व छात्रा होने के नाते मुख्यमंत्री के लिए यह अवसर भावनात्मक रहा। परिसर में उन्होंने छात्र जीवन की यादें साझा

करते हुए बताया कि कॉलेज छात्रसंघ की जनरल सेक्रेटरी बनने के साथ उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। छात्र राजनीति में मिली जिम्मेदारियों ने उन्हें लोगों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने

कहा कि छात्र जीवन में छात्राओं और विद्यार्थियों के हित में उठाए गए मुद्दों को आज व्यापक स्तर पर हल करने का अवसर मिला। उनके लिए संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में एक लाइट स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाने और उन्हें कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही 50 हजार नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य निगरानी व्यवस्था मजबूत करना और महिलाओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने जोर दिया कि लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल उन पर डालना उचित नहीं है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और लड़कियों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय लड़कों और पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा। कार्यक्रम के दौरान महिला विकास समिति की छात्राओं ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं के साहस, आत्मविश्वास और तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण लड़कियों को संकट की स्थिति में अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार करने के साथ उनमें आत्मविश्वास और निर्भीकता भी विकसित करता है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करता है या उन्हें डराने की कोशिश करता है, तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए।

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में जन सुनवाई में शामिल हुए राहुल गांधी, चार बूथों से 416 नाम हटाने का आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में ऊपर के स्तर से वोट चोरी की जा रही है और गरीबों के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष तब तक अपना आंदोलन जारी रखेगा, जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते।

राहुल गांधी मंगलवार को यहां त्रिलोकपुरी स्थित ब्लॉक-20 में ‘वोट अधिकार जीने का अधिकार’ जन सुनवाई में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं। राहुल ने दावा किया कि जन सुनवाई में सामने आया कि चार बूथों से 416 लोगों के नाम गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि वोट देना भारत के हर वयस्क नागरिक का अधिकार है, लेकिन करोड़ों लोगों से यह अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के नाम मतदाता सूची से हटाकर उनके अधिकार और



सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रहा है और अब लोग भी समझ रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, विपक्ष एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। उल्लेखनीय है कि मतदाता

सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग जैसी प्रक्रिया आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके बाद एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा प्रस्तावित है।

प्रदूषण की रोकथाम के लिए एमसीडी की तैयारी तेज, 700 हॉपर पिकर्स होंगे तेनात : सत्या शर्मा

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए तैयारी तेज करते हुए 700 हॉपर पिकर्स तेनात करने की घोषणा की। एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि वायु प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम धूल नियंत्रण, सड़कों की सफाई, कचरे के निस्तरण और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई तेज कर रहा है। एमसीडी के पास फिलहाल 66 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, 167 वाटर स्प्रंकलर और 28 एंटी स्मॉग गन कार्यशील हैं।

सभी जोन में इनके इस्तेमाल के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं। सत्या शर्मा ने बताया कि सड़क की धूल कम करने के लिए इस वर्ष 1,202 किलोमीटर सड़कों के पुनर्वास और सुधार का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी से सितंबर तक 745 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। अप्रैल से सितंबर के बीच 8,141 गड्ढों की मरम्मत कर 17,132 वर्ग मीटर सड़क क्षेत्र दुरुस्त किया गया। विशेष अभियान के तहत 3,750 मीट्रिक टन सिल्ट भी हटाई जा चुकी है। सत्या शर्मा के अनुसार, सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए नई मशीनों की तेनाती की जा रही है। चार घन मीटर क्षमता वाले 15 सीएनजी और दो घन मीटर क्षमता वाले 55 इलेक्ट्रिक एमआरएसएम वाहनों के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। इन्हें नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से तेनात करने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, 31 दिसंबर तक 700 हॉपर पिकर्स तेनात करने का लक्ष्य है। हाल ही में खरीदे गए 12 वाटर स्प्रंकलर और एंटी स्मॉग गन भी जल्द तेनात किए जाएंगे। सत्या शर्मा ने बताया कि नैसर्गिक एवं विध्वंस मलबे के वैज्ञानिक निस्तरण के लिए एमसीडी ने ‘शहरी मलबा’ ऐप शुरू किया है। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 5,000 से 6,000 मीट्रिक टन निर्माण मलबा निकलता है। वहीं, अप्रैल से सितंबर तक निगम क्षेत्र में 1,34,029 पेड़ और 2,74,465 झाड़ियां लगाई गईं।

एमसीडी स्कूलों में 50 हजार नए दाखिले का लक्ष्य, हर स्कूल में लगेंगे पांच स्मार्ट बोर्ड

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की शिक्षा समिति की बैठक में निगम के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। शिक्षा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट योगेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 50 हजार नए दाखिलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को चालू माह में कम से कम 30 नए बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्कूल चलो अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने, बच्चों को नैतिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा देने, विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करने, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने पर विशेष जोर दिया गया। अध्यक्ष ने अधिकारियों को सभी निर्णय निर्धारित समय-सीमा में लागू करने के निर्देश दिए।

बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनमें नैतिक मूल्यों की विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षाविदों की एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति के गठन का अधिकार शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा को दिया गया है। यह समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में नैतिक मूल्यों, अनुशासन, सामाजिक

मिलावटी मिठाई से सावधान ! दयालपुर गांव में कथित अवैध फैक्ट्री का कारोबार, खाद्य सुरक्षा पर उठे सवाल

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में मेन करावल नगर रोड स्थित अंबेडकर चौपाल के सामने दयालपुर गांव की बड़ वाली गली में कथित तौर पर बिना आवश्यक अनुमति के मिठाई बनाने का कारोबार संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के दावों के अनुसार, एक जर्जर मकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां तैयार कर बाजार में आपूर्ति की जा रही है। इन मिठाइयों की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की मांग स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित परिसर में तैयार की जा रही मिठाइयों में कथित तौर पर मिलावटी या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सामग्री का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। हालांकि, मिठाइयों में मिलावट की पुष्टि प्रयोगशाला की जांच और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद ही हो सकती है। त्योहारों और शादी-विवाह के मौसम में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। यदि उक्त पहसर में मिठाई निर्माण का काम बिना आवश्यक लाइसेंस के हो रहा है, तो इसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

बिना अनुमति कारोबार चलने के आरोप

विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि संबंधित परिसर में मिठाई निर्माण के लिए आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में संबंधित विभागों को शिकायतें भी दी गई हैं, लेकिन कथित कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ रही है। हालांकि, संबंधित परिसर के लाइसेंस, अनुमतियों और विभागीय कार्रवाई की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि किया जाना आवश्यक है। किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी की मिलीभगत अथवा रिश्तखोरी के आरोपों की पुष्टि भी निष्पक्ष जांच के बाद ही की जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर निगाहें

क्षेत्रवासियों ने दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग, संबंधित नगर निगम अधिकारियों और जिला प्रशासन से मामले का सज्ञान लेने की मांग की है। उनकी मांग है कि परिसर का निरीक्षण किया जाए, वहां तैयार की जा रही मिठाइयों के नमूने लेकर अधिकृत प्रयोगशाला में जांच कराई जाए और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों में मिलावट उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाना जरूरी है।

प्रशासन से उठे सवाल

दयालपुर गांव की बड़ वाली गली में कथित रूप से संचालित मिठाई निर्माण इकाई को लेकर अब संबंधित विभागों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। यदि शिकायतों से बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब देखना यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाते हैं या नहीं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि समय रहते उचित कार्रवाई होगी, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकेगी।

दिल्ली की जिला अदालतों में मंगलवार को वकीलों ने किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार

नई दिल्ली। दिल्ली की सभी जिला अदालतों में मंगलवार को वकील न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशंस की को-आर्डिनेशन कमिटी ने शाहदरा थाने में वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार और धमकी देने की घटना के विरोध में न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान किया। आज कड़कड़झाा कोर्ट के वकीलों ने पूर्वी दिल्ली के ज्वाइट कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन किया और एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और निष्पक्ष जांच पूरी होने तक संबंधित एसएचओ के तत्काल निलंबन की मांग की। ये मामला वकील ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट लगने की घटना से जुड़ा है। को-आर्डिनेशन कमिटी का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जब वकील पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके साथ कथित तौर पर धमकी भरा व्यवहार किया गया। इस मामले में वकील अमूल्य रतन शिकायतकर्ता हैं। को-आर्डिनेशन कमिटी ने कहा है कि चोट की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों से तत्काल, प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा थी। 23 अक्टूबर को शाम कई वकील शाहदरा थाना पहुंचे और घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कमिटी के मुताबिक उस समय एसीपी और थाना प्रभारी ने वकीलों को भरोसा दिलाया था कि आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि 24 अक्टूबर को जब वकील दोबारा थाने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि संबंधित आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया था और कथित तौर पर उन्हें छोड़ दिया गया था। इससे वकीलों में गंभीर नाराजगी पैदा हुई। कमिटी के अनुसार, जब अधिवक्ता मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताने और जवाबदेही तय करने की मांग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने कथित तौर पर अपना रिवाल्वर दिखाया और वहां मौजूद वकीलों को धमकाया।

भाजपा का ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान वोट चोरी और सीनाजोरी का उदाहरण: देवेंद्र यादव

शबाना बेगम , सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 28 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा लाल किले से टाउन हॉल तक निकाले जाने वाले मार्च पर सवाल उठाते हुए इसे ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नाम पर वोट चोरी और सीनाजोरी का उदाहरण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का यह मार्च ऐसे समय में निकाला जा रहा है, जब देशभर में मतदाता सूची और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तथा। उन्होंने आरोप लगाया कि रामलीला मैदान में महाठबंभन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली प्रस्तावित है।

देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा का यह कदम जनता को भ्रमित करने और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कथित हेरफेर और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा राजनीतिक अभियान चला रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि करवा चौथ और त्योहारों के मौसम में चांदनी चौक जैसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में मार्च निकालने से छोटे-बड़े व्यापारियों के कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि इससे दुकानदारों के



साथ-साथ वहां काम करने वाले श्रमिकों की रोजी-रोटी भी प्रभावित हो सकती है। यादव ने भाजपा पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर पार्टी व्यापारियों के हितों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर व्यस्त बाजार में राजनीतिक मार्च निकालने का निर्यण लेती है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब विपक्षी दलों के कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के लिए अनुमति मिलने में कठिनाइयां आती हैं, तो भाजपा को इस मार्ग पर मार्च निकालने की अनुमति कैसे मिल गई। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले छात्रों और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने, मेट्रो के प्रवेश और निकास द्वारों को बंद करने तथा सार्वजनिक परिवहन बसों

को रोकने जैसे कदम उठाए थे। उनके अनुसार, इन कदमों से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली प्रस्तावित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली की तैयारियों का जवाब देने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के वरिष्ठ नेताओं के साथ मैदान का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि मताधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए चल रहा अभियान रुकने वाला नहीं है। यादव ने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और विपक्षी दलों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव के आगे विपक्ष न रुकेगा और न झुकेगा। यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।

प्रीत विहार-निर्माण विहार में कथित अवैध निर्माणों की बाढ़, निगम कर्मचारी पर उगाही और फर्जी हजिरी के आरोप

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन में कथित अवैध निर्माणों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रीत विहार, निर्माण विहार, मधु विहार, आईपी एक्सपेंशन, आनंद विहार और डिफेंस एन्क्लेव सहित कई इलाकों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग को जानकारी दिए जाने के बावजूद कई निर्माण स्थलों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। मामले में निगम के अभियांत्रिकी डिवीजन-2 के अंतर्गत प्रीत विहार स्थित निगम स्टोर पर तेनात मेट प्रवीण उर्फ मौनू की भूमिका को लेकर भी शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, संबंधित कर्मचारी पर कथित अवैध वसूली और कुछ कर्मचारियों की फर्जी हजिरी से जुड़े आरोप हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित कर्मचारी का पक्ष सामने आना बाकी है।

तबादले के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं करने का आरोप

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि संबंधित मेट का पहले भी कई बार तबादला किया जा चुका है। वर्तमान में उनका तबादला एसएलएफ में किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन आरोप है कि उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि तबादले से संबंधित रिकॉर्ड, उपस्थिति रजिस्टर और ड्यूटी संबंधी दस्तावेजों की जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

आठ स्थानों पर बहुमंजिला निर्माण की शिकायतें

शिकायतकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, प्रीत विहार और आसपास के क्षेत्रों में कई संपत्तियों पर कथित अनधिकृत निर्माण की शिकायत की गई है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित मामले शामिल हैं:

प्रीत विहार क्षेत्र

संपत्ति संख्या ए-139: तीन मंजिला निर्माण पूरा होने और अंदर फिनिशिंग का काम जारी रहने का आरोप।

संपत्ति संख्या डीओ-117: पांच मंजिला निर्माण होने का दावा।

अन्य संपत्तियां: कुछ भवनों में स्वीकृत नक्शे और

निर्माण की वास्तविक स्थिति की जांच की मांग की गई है।

मधु विहार और आसपास के क्षेत्र

मधु विहार, एसबीआई के निक्ट, संपत्ति संख्या ए-64: पांच मंजिला निर्माण जारी होने का आरोप।

डिफेंस एन्क्लेव, संपत्ति संख्या-29: पांच मंजिला भवन का निर्माण जारी होने की शिकायत।

निर्माण विहार और अन्य इलाक़े: शिकायतकर्ताओं ने कुछ अन्य स्थानों पर भी बहुमंजिला निर्माण की जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन संपत्तियों की वास्तविक स्थिति, स्वीकृत भवन योजनाओं और निर्माण संबंधी अनुमतियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित निर्माण नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

निगम की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं के अनुसार, कथित अवैध निर्माणों को लेकर लिखित शिकायतें और तस्वीरें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई हैं। इसके बावजूद कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है।

एक नगर

300 किलो पटाखे बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद **फरीदाबाद** **क्राइम** **ब्रांच**
डीएलएफ और सेक्टर-48 की टीम ने मंगलवार को अवैध रूप से बेचे जा रहे करीब 300 किलो पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने अनुसार, क्राइम ब्रांच 'वॉर्डर की टीम को सूचना मिली थी कि न्यू जैन कॉलोनी, एनआईटी निवासी कपिल वाम 'इको गाड़ी में पटाखे लेकर अवैध रूप से बेचने जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। उसके कब्जे से 125 किलो प्रतिबंधित पटाखे मिले। दूसरे मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने ओल्ड फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी से नरेंद्र नाथ के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 104 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए। जबकि सेक्टर-48 की टीम ने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी मुहम्मद माथुर को सेक्टर-48 मार्केट के पीछे से पकड़ा। उसके कब्जे से 35 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। पुलिस अब इन लोगों से सप्लाय चैन के बारे में पता कर रही है। प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि ये लोग किन-किन को अपना माल बेच रहे थे। इस माल को ये लोग कहाँ से खरीदकर लाते थे।

नूंह मेडिकल कॉलेज का सहायक 22 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

नूंह। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की नूंह सब-यूनिट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहीद हसन खान राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हडू के डीन कार्यालय में तैनात एक सहायक को 22 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एग्जेंसी हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप की पहचान सकरद्दीन के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता की छह दिनों की अतिरिक्त व्यूटी की हाजिरी पूरी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। ब्यूरो के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि शिकायतकर्ता ने एसीबी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज के डीन कार्यालय में सहायक के पद पर तैनात सकरद्दीन उससे अतिरिक्त व्यूटी की छह दिनों की हाजिरी पूरी करने के एवज में 22 हजार रुपये मांग रहा था। शिकायत के आधार पर एसीबी की नूंह सब-यूनिट ने नियमानुसार ट्रैप की योजना बनाई। इसके बाद एसीबी की टीम ने नकाराई रिश्वत हासिल की को कथित तौर पर 22 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एग्जेंसी हाथ पकड़ लिया। मामले में आरोपी के खिलाफ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के गुरुग्राम थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसीबी की ओर से मामले की आगामी जांच नियमानुसार की जा रही है। एसीबी ने आज्ञाजन्य अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य को करने के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत ब्यूरो को दें। इसके अलावा नागरिक 'सतर्क विवेचरण' मोबाइल ऐप के माध्यम से भी भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

नूह में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टरों पर पुलिस की सख्ती, चलेगा विशेष अभियान



नूंह। जिले में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह पुलिस ने सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अप्पित्त राजेन के निर्देश पर बुधवार से बिना पंजीकृत नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रैक्टरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर प्लेट और पेंट नंबर लिख कर चलाए गए ट्रैक्टरों पर विशेष अभियान चलाया जायेगा और नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और यातायात पुलिस को अपने-अपने क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत विशेष रूप से ऐसे ट्रैक्टरों की जांच की जाएगी, जिन पर नियमानुसार पंजीकृत नंबर प्लेट नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि पुलिस के सज्ञान में आया है कि जिले में कई ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर चल रहे हैं। कुछ ट्रैक्टरों पर नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं देते, जबकि कुछ पर नंबर प्लेट लगाने के बजाय पेंट से ही नंबर लिखे गए हैं। पुलिस के अनुसार स्पष्ट किया है कि पेंट से लिखे गए नंबर पंजीकृत नंबर प्लेट का विकल्प नहीं हैं। वाहन पर नियमानुसार निर्धारित नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जिन ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, प्लेट स्पष्ट होगी या नंबर पेंट से लिखे गए होंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी। एसके लिट संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बुधवार से शुरू होने वाला यह अभियान जिले में लगातार चलाया जाएगा।

गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय का बदलेगा ठिकाना, 92 करोड़ के बजट से तैयार होगा 7 मंजिला हाई टेक ऑफिस



जायेगा। अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए भवन का निर्माण किया जायेगा। सात मंजिला ऑफिस बनाने के साथ पार्किंग भी बनाई जाएगी। जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जायेगी। वर्तमान ऑफिस में सिटी जोन का कार्यालय बनाया जाएगा। सिटी जोन कार्यालय इन दिनों सामुदायिक केंद्र में चल रहा है। नगर निगम

ने स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया है। नगरायुक्त विक्रमामित्य सिंह मलिक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का भी जल्द ही भूमि पूजन कराया जायेगा। यह स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स आने वाले समय में आकर्षण का केंद्र बनेगा। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के होने से शहर की प्रतिभाओं को बेहतर लाभ मिलेगा। केंद्र

गुरुग्राम पुलिस ने सवा करोड़ का 673 किलो गांजा पकड़ा, दो गिरफ्तार

गुरुग्राम स्थानीय पुलिस ने नशा तस्करी के खेलपाक बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से भेरीबाड़ी ले जाया जा रहा 673 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजा की कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने मंगलवार को बताया कि आरोपी प्लास्टिक दानों के बैगों के बीच गांजा छुपाकर सप्लाई करने जा रहे थे, लेकिन गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी से नाकाम हो गए। जानकारी के अनुसार अपराध शाखा सेक्टर-25 के ईंचार्ज अनु-नरीक्षक अरुण की ने 26/26 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि को गाजीव चौक के पास गश्त पर थी।

इसी दौरान विक्कसर्वाय सूत्रा से सूचना मिली कि राजस्थान नंबर के एक टाटा ट्रक में चालाक छिपाकर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध ट्रक पर नजर रखी और राजीव चौक के पास उसे रुकवाकर जांच की। ट्रक में चालक साहब और क्लीनर सनावर चौधरी मिले। नियमानुसार तलाशी लेने पर ट्रक में लास्टिक दानों की बोरियों के नीचे नशीला द्रव्य छिपा मिला। पुलिस ने ट्रक से माला उतरवाया तो 23 बैगों में भरा 673 किलोग्राम

गंगा बरामद हुआ। इसके अलावा पूरे में भरपूर प्लास्टिक दानों के 767 बैग, 15 टोंट और प्लास्टिक स्की में प्रयोग टाटा डूक भी कब्जे में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 34 वर्षीय अशोक साबिर निवासी गांव उदयपुर जिला खैरथल (राजस्थान) और 19 वर्षीय सनावर निवासी गांव मिर्जापुर जिला खैरथल के रूप में हुई है। गाँव जांच में सामने आया कि ट्रक साबिर का ही है और वह खुद चालक है। उसने सनावर को 20 हजार रुपये महती पर क्लीनर रखा हुआ था। साबिर गाँजा लेने के लिए प्लास्टिक से उड़ीसा करने जा रहा था। प्रथमिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे उड़ीसा से गाँजा भरकर भिवाड़ी राजस्थान करने जा रहे थे, प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे उड़ीसा से गाँजा भरकर भिवाड़ी राजस्थान करने जा रहे थे। इसके लिए उन्हें उनके अन्य साथियों द्वारा दो लाख रुपये दिए जाने थे। आरोपी पहले भी दो बार उड़ीसा तरह प्लास्टिक दानों के बीच गाँजा छुपाकर सप्लाई कर चुके हैं। यह तीसरी बार थी। इस संबंध में थाना सदर गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब उसने गाँजे की सप्लाई के स्रोत, डिलीवरी और इस नेवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।

10 लाख विद्यार्थियों तक पहुंचेगा वैज्ञानिक योग, डाइट पाली में तैयार हो रहे योग प्रशिक्षक

फरीदाबाद। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का अभियान अब धरातल पर उठाने लगा है। हरियाणा योग आयोग, शिक्षा विभाग, हरियाणा एवं पंतजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) पाली, फरीदाबाद में चल रहे 30 दिवसीय योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को हरियाणा योग आयोग से आशीष ने निरीक्षण किया तथा प्रतिभागी शिक्षकों से संवाद केया। आशीष ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में लगभग 10 लाख विद्यार्थियों तक योग पहुँचाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने प्रदेशभर में 10,500 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, यानी प्रत्येक प्रशिक्षित शिक्षक औसतन लगभग 95 विद्यार्थियों को नियमित योगाभ्यास करवाएगा।

प्रथम चरण (21 अक्टूबर से 4 नवंबर)
में 23 जिलों के लगभग 1,700 शारीरिक
शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनकी औसत
उपस्थिति 92 प्रतिशत से अधिक है।
फरीदाबाद में 52 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर
ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. जयदीप आर्य इस
कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, जिनका जीवन योग

जब चुनाव बेमानी हों तो ट्रेड एसोसिएशन व्यापारियों की चिंता का दिखावा ना करे: अशोक बुवानीवाला

गुरुग्राम। कांग्रेस की एक नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली को दिल्ली की ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा रद्द करने की मांग को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवाणीवाला ने राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समर्थन से चल रही ट्रेड एसोसिएशन को सरकार द्वारा व्यापारियों के खिलाफ लागू किए गए नियम, कानून नजर नहीं आते। उन्होंने कहा नजर नहीं आता कि भाजपा सरकार में मंत्री देशभर में रोड शो करने निकलेंगे, उससे भी व्यापार प्रभावित होगा। बीजेपी सरकार के निर्णयों के रोड शो भी दिवाली से पहले ही होने लगे। मुंगलवार को यहां जारी बयान में अशोक बुवाणीवाला ने कहा कि जब चुनाव ही बेमानि हो गए हों और फैसले व्यापारी या कुटीर उद्योग के पक्ष में हो ही नहीं रहे हों तो इस तरह के संगठनों का व्यापारियों को चिंता करना मजबूर दिखावा है। बुवाणीवाला ने कहा कि पिछले बाराह साल में बीजेपी की नीतियों ने देश के छोटे व्यापार, खुदरा व्यापारी और कुटीर उद्योग को पूरी तरह तबाह कर दिया है। नोटबंदी से लेकर

विश्व में हिमालय की तरह ऊँचा उठाने
लिए समर्पित हैं। योगासन को खेल के
में स्थापित करना हो, योग का वैज्ञानिक
संस्थान हो, घर-घर योग पहुँचाने का
उत्पन्न हो या शिक्षा के क्षेत्र में योग की
नयी क्रांति – ये सभी डॉ. आर्य के पुरुषार्थ
देन हैं। उनके विजुन के अंतर्गत कुरुक्षेत्र
लगाया 10 एकड़ में विश्व स्तरीय
इंटरनेशनल हॉल प्रस्तावित है तथा वर्ष 2036
भारत की ओलंपिक मेजबानी के दौरान
योगासन एवं कबड्डी को ओलंपिक में
मेल करना एवं और योगासन में 28 पदक
प्रकाश रखा गया है। योग के वैज्ञानिक पक्ष
प्रकाश डालते हुए आशीष ने बताया कि

विद्यार्थियों में हुए अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों (रैंडमाइड कंट्रोलड ट्रायल नियमित योगाभ्यास करने वाले विद्यार्थी में भवनात्मक संतुलन, आनंद-नियंत्रण, आक्रामता में सुधार तथा तनाव और चिन्ता उल्लेखनीय कमी पाई गई है। कुछ अध्ययनों में 10 सप्ताह के योगाभ्यास के बाद बिना तनाव हाईलैंड कॉर्टिसोल के स्तर में निम्न दर्ज की गई। प्राणाग्या एवं ध्यान से शक्ति, क्षमता, स्मरण शक्ति और निर्णय बेहतर होती है। इसी आधार पर प्रशिक्षण, आसन, प्राणाग्या एवं ध्यान के साथ शारीरिक व मानसिक प्रभावों का वैज्ञानिक आधार भी समझाया जा रहा है।

वैज्ञानिक
मेग पशिक्षक

फरीदाबाद। गांव मुजुसर में इमारत की पहली मंजिल पर वेल्डिंग का काम कर रहे समय मंगलवार को हादसा हो गया। मजदूरों के काम करने के लिए पैगल अचानक से टूट गया। जिससे तीन मजदूर नीचे गिर गए। घायल हालत में सभी को इलाज के लिए बीके अस्पताल लेकर जाया गया। जहां से उनको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। यहाँ मजदूरों के साथ बीके अस्पताल पहुंचे ठेकेदार असरद ने बताया कि वह मुजुसर में एक इमारत की पहली मंजिल पर वेल्डिंग का काम कर रहे थे। यहाँ फ्लिकिंग का स्टार बन रहा है। जिसके लिए बोर्ड सहित दूसरा काम किया जा रहा था। इसी दौरान पैगल अचानक से टूट गया और तीन मजदूर नीचे आकर गिर गए। असरद ने बताया कि घायलों में मुजुसर, साहिब और फहील शामिल हैं। तीनों ही सहारनपुर युपी के रहने वाले हैं। तीनों के पैर और सर में चोट आई है। जानकारी के मुताबिक पहली मंजिल से गिरने के बाद तीनों नीचे लगी एक ठोस शेड पर गिरे थे जिस कारण एक बीना हादसा होने से टल गया।

वाहन चोरी गैंग का भंडाफोड़, चोरी की पांच मोटरसाइकिल बरामद

फरीदाबाद। जिला पुलिस की अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने गाँव गाँव का एक वाहन चोरी के मौक़ा का भंडाफोड़ करते हुए उसके दो सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सदस्यों की पहचान मोहित व सुमित निवासी गाँव मेवला महाराजपुर फरीदाबाद के रूप में हुई है। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाला अनुराग भी मेवला महाराजपुर का रहने वाला है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार निरीक्षक अनिल, प्रभारी अपराध शाखा एनआईटी के नेतृत्व में एसआई कुलदीप, हेड कांस्टेबल हरपाल, संदीप, कांस्टेबल सुमित व राहुल की टीम ने थाना सेक्टर-31 क्षेत्र के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल

चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 22 अक्टूबर को मोहित निवासी गांधी मेवला महाराजपुर के गिरफ्तार किया था। उन्होंने आगे बताया कि टीम द्वारा मोहित को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने साथी सुमित के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देता था तथा चोरों की मोटरसाइकिल को आठ हजार रुपये में अनुराग को बेच दिया। जिस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच आईआईटी की टीम ने उसके साथी सुमित व चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले अनुराग को भी गिरफ्तार कर लिया है। अनुराग से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मोहित व सुमित की पूछताछ में अन्य स्थलों से भी वाहन चोरी करने का बात सामने आई।

10 दिन में 40 हजार ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को किया आवेदन, बीएलओ पर कार्रवाई



जाएगी। बीएलओ की ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भाखरी से हटेगा कूड़ा, प्रतापगढ़ डंपिंग प्लांट की बढ़ेगी क्षमता : कृष्णपाल गुर्जर

कूड़ा डालने को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच गतिरोध बना हुआ है। बैठक के बाद कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि सेक्टर-56 के प्रतापगढ़ में 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया है। इसका क्षमता बढ़ाकर 750 टन प्रतिदिन करने की तैयारी है। इसके अलावा मुजेंरी में 200 टन क्षमता का कूड़ा निस्तारण प्लांट भी चल रहा है। मंत्री के मुताबिक, शहर में जहां भी बड़े कूड़ा कलेक्शन प्लांट हैं, वहां कूड़े के निस्तारण के लिए मशीनें लगाए जाएंगी। इससे कूड़े का निस्तारण और स्थान पर किया जा सकेगा। उसी भाष्य में जमा कूड़े को हटाने का रास्ता साफ होगा। हालांकि, भाखरी से कूड़ा हटाने का काम कब और कितनी तेजी से शुरू होगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। स्मार्ट सिटी में विभिन्न स्तरों से रोजाना करीब 1200 टन कचरा निकलता है। बंधवाड़ी में कूड़ा फेंकने पर रोक लगने के बाद नगर निगम के सामने कूड़ा डंपिंग को लेकर समस्या बढ़ गई है। प्रतापगढ़ निस्तारण केंद्र में विधायक के हस्तक्षेप के बाद पांच ट्रक से ज्यादा कूड़ा नहीं डाला जा सकता है।

नूंह में अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती, 30.51 लाख जुर्माना वसूला

नूंह। नूंह जले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 वाहनों को जब्त कर संबंधित मामलों में 30 लाख 51 हजार 150 रुपये की पेनल्टी वसूल की है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गिराना बढ़ाने और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उपायुक्त अखिल पिलानी मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्सेस हॉल में खनन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए 41 वाहनों में 21 वाहन बिना ई-रवाना के खनिजों का परिवहन करने हुए पकड़े गए, जबकि 20 वाहन अंतरराष्ट्रीय परिवहन पास (आईएसटीपी) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में पकड़े गए। इन मामलों में कुल 30,51,150 रुपये की पेनल्टी वसूली गई है।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन को किसी भी सूत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी



गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ लगातार निगरानी रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

प्रशासन की प्राथमिकता अवैध खनन और खनिजों के अनधिकृत परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना है। उपायवत्तन नै अधिकायियों को निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन या खनिजों के अवैध परिवहन से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का अभियान अग्रे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।

कश्मीर के विलय और पूर्ण एकीकरण में रास्व संघ की भूमिका

डॉ. पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके वैचारिक सहयोगियों ने कश्मीर के पूर्ण एकीकरण से जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण और स्थायी भूमिका निभाई, जिसे अक्सर पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह कठिन स्थिति में थे। एक कट्टर और देशभक्त हिंदू होने के नाते वे पाकिस्तान में शामिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे लेकिन राज्य में मुस्लिम आबादी की बड़ी संख्या ने उन्हें असमंजस में डाल दिया था। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा को पाकिस्तान बनने के लिए मानने के उद्देश्य से कश्मीर का दौरा किया लेकिन महाराजा ने इस दबाव को ठुकरा दिया। उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे आर.सी. बाबू ने महाराजा को स्वतंत्र बने रहने की सलाह दी। इस जटिल स्थिति की बीच संघ ने महाराजा का समर्थन किया और उनके राज्य के भारत में विलय की वकालत की। संघ ने 1940 के दशक में जम्मू-कश्मीर में अपना काम शुरू किया। दिवंगत प्रो. बलराज मधोक के नेतृत्व और प्र. प्रेमानाथ डोगरा के मार्गदर्शन में संगठन ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। जब महाराजा पर पाकिस्तान को आने से विलय के लिए दबाव बढ़ता गया तो उनके सामने तीन विकल्प थे: पाकिस्तान में शामिल होना, भारतीय संघ में विलय करना या स्वतंत्र बने रहना। वे पाकिस्तान में शामिल होने के तो खिलाफ थे ही लेकिन प्र. नेहरू द्वारा शेख अब्दुल्ला को दिए जा रहे समर्थन को लेकर वे भारतीय संघ में शामिल होने को लेकर भी आशंकित थे। वहीं, स्वतंत्र बने रहना भी जोखिम भरा हो सकता था क्योंकि इससे पाकिस्तान के हमले का खतरा था और पर्याप्त सुरक्षा न होने के कारण यह एक खतरनाक विकल्प साबित हो सकता था।

इस दौरान, महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल के करीबी महारजद महानजन को अपना नया प्रचारमंत्री नियुक्त किया। महानज, जिनके जम्म्- कश्मीर में आरएसएस प्रचारक थीं. बरराज मधोक के साथ अच्छे संबंध थे, ने महाराजा को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इसमें पाकिस्तान या भारा में शामिल होने के फायदे और युक्तान तथा स्वतंत्र बने रहने के विकल्प के बारे में बताया गया था। मधोक ने महाराजा को आरएसएस की ओर से पूरा समर्थन देने का भी वादा किया। उसी समय, तत्कालीन गवर्नर- जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा पर पाकिस्तान के साथ विलय का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दबाव डाला लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इस बीच, पाकिस्तानी अधिकारी अपनी सेना की मदद से कबायलियों के समूहों के जरिए कश्मीर पर हमला करने की योजना बना रहे थे, जिससे महाराजा के लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो गया। अपने दरबारियों, सहयोगियों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बढ़ते दबाव के बीच- जो कश्मीर के भारत में विलय की क्वालत कर रहे थे- सरदार पटेल और महात्मा गांधी दोनों ने महाराजा को मानने की कोशिश की लेकिन महाराजा अपनी बात पर अड़े रहे और नेहरू के प्रभाव में आने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना कश्मीर की सीमाओं तक

पहुँच गई थी, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। राजनीतिक बातचीत विफल होने पर सरदार पटेल ने मेहरचंद महाजन के जरिए आरएसएस के सरसंघचालक एम. एस. गोवलकर को एक संदेश भेजा। इसमें उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके महाराजा को भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित करें।

गोलवलकर जुड़े, जिन्हें प्यार से 'गुरुजी' कहा जाता था ने एक संवेदनशील मोड़ पर बाद करने के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और तुरंत नागपुर से इलहा हो गए श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। मेहरचंद महानाथ और पंडित प्रेमनाथ डोगरा की मदद से गुरुजी और महाराजा हरि सिंह के बीच बैठक तय की गई। उस समय पंजाब और जम्मू-कश्मीर के प्रांत प्रचारक रहे स्वर्गीय भावलराम मुले ने बताया कि गोलवलकर गुरुजी, महाराजा को भारत में मिलवय (एक्सेशन) पर विचार करने के लिए मनाने में सफल रहे। इसके बाद, महाराजा ने भारत में विलय का

प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया, जबकि गुरुजी ने जम्मू-कश्मीर में आरएसएस (आएसएस) कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। वे निर्देश देने के बाद, वे दिल्ली लौट आए। मुले ने अपनी पुस्तक 'श्री गुरुजी समग्र दर्शन' में इस महत्वपूर्ण घटना का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय गुरु मंत्री सदाशिव पेडले ने मेहरचंद महाजन से कहा था कि वे गुरुजी से बात करें ताकि महाराजा हरि सिंह को राज्य के भारत में विलय के लिए तैयार किया जा सके। महाजन ने यह संदेश गुरुजी तक पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी बैठक आयोजित हुई।

गुरुजी 17 अक्टूबर 1947 को दिल्ली से विमान द्वारा श्रीनगर पहुँचे और अगली सुबह, 18 अक्टूबर को बैठक हुई। इस बैठक में राजकुमाराराज करण सिंह भी मौजूद थे, जो पैर में फ्रैक्चर के कारण प्लास्टर बंधे होने की वजह से बिस्तर पर लेटे हुए थे। महाराजा ने अपना यह विचार व्यक्त

किया कि उनका राज्य पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर है। उन्होंने कहा, 'सभी रास्ते सियालकोट और रावलपिंडी से होकर गुजरते हैं। लाहौर में?' हुजवी अंशु है। ऐसे में मैं भारत के साथ संबंध कैसे रख सकता हूँ?' गुरांजी ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, 'आप एक हिंदू राजा हैं। पाकिस्तान के साथ जुड़ने पर आपकी हिंदू प्रजा को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भले ही अभी कोई रास्ता मौजूद न हो लेकिन उन्हें जल्दी ही बहाल किया जा सकता है। भारत में विलय करना आपके और जम्मू-कश्मीर, दोनों के हित में होगा।'

प्रथममन्त्री महाजन ने भी गुरुजी की बात का समर्थन किया और भारत में विलय की आवश्यकता पर जोर दिया। अपनी मुलाकात के अंत में, महाराजा ने गुरुजी को एक 'तोसा' (उच्च गुणवत्ता वाला पश्मीना शॉल) भेंट किया और भारत में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई। आठ दिन बाद, महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। उस समय संघ के सरसंघचालक रहे गोवलकर गुरुजी ने महाराजा को मनाने और इस विलय को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई। हालाँकि, इतिहास के इस महत्वपूर्ण घटना को काफी हद तक अनेच्छा कर दिया गया है, जिस कारण यह लोगों की यादों से मिट गई है। जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में संघ की भूमिका पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि संघ के प्रयासों की बदौलत ही आज जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है।

पाकिस्तान समर्थित कबायलियों के हमले के दौरान संघ स्वयंसेवकों ने भारतीय सेना की मदद के लिए भारी बलिदान दिए; इन्हीं प्रयासों की वजह से जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाया जा सका। अक्टूबर 1947 में अशांति के दौर में जम्मू में संघ स्वयंसेवकों और स्थानीय राष्ट्रवादी स्वयंसेवकों ने नागरिक प्रशासन की मदद करने, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और पाकिस्तानी कबीलें हमलों के कारण विस्थापित हुए शरणार्थियों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रजा परिषद आंदोलन (1952-1953): पंडित प्रेम नाथ डोगरा जैसे नेताओं के नेतृत्व में और संघ तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'भारतीय जनसंघ' के वैचारिक समर्थन से जम्मू प्रजा परिषद ने 'परमिट प्रणाली' और जम्मू-कश्मीर के लिए 'दो इंडेंडेड संविधान' वाली व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सर्वोच्च बलिदान: 1953 में श्रीनगर की जेल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरफ्तारी और रहस्यमय मौत— जो उस समय 'परमिट नियम' (नारा: 'एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान— नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे') का विरोध कर रहे थे, ने पूरे देश में एक नई भावना जगाई। इसने राष्ट्रवादी एजेंडे के तहत कश्मीर के पूर्ण विलय की मांग को और अधिक मजबूत कर दिया। 1990 के दशक में आतंकवाद के चरम दौर के दौरान संघ से जुड़े संगठनों— जैसे सहकार भारती, सेवा भारती और विभिन्न शैक्षिक ट्रस्टों ने घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। साथ ही, उन्होंने जम्मू क्षेत्र में राष्ट्रवादी एकता की भावना को भी बढ़ावा दिया।

हरियाणा उस समय एक शुष्क और धूल भरा इलाका था—जिसे कमतर माना जाता था, जहां न के बराबर उद्योग-धंधे, सड़कें थीं और नहरें भी नहीं थीं, और न ही पैसा था। कल गया था कि कुछ ही सालों में यह राज्य असफल होकर रह जाएगा, कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएगा। यह लकीर 1961 की जनगणना आधारित थी। इसी जनगणना के आंकड़ों से यह तय होना था कि पूर्वी पंजाब के मैदानी इलाकों में हर गांव और शहर का भविष्य का पता क्या होगा। जब जनगणना करने वाले अधिकारी आए तो मेरे माता-पिता—जो कि पश्चिमी पंजाब से आकर यहां बसे थे—ने अपनी मातृभाषा 'हिंदी' बताई। यह प्यार से बोला गया झूठ था; एक ऐसे राज्य के लिए दिया गया वोट, जिसका उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था। जब हरियाणा बना, तब मैंने अंबाला शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी, जहां हर कोई पंजाबी बोलता था। कुछ ही समय बाद, हिंदी में किताबें आ गई—एक ऐसी भाषा जिसे मेरे शिक्षकों और मैंने एक साथ मिलकर सीखा। बाद में, कॉलेज में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी हो गया। कई सालों तक, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मुझे दिमाग में तीन कदम उठाने पड़ते थे—पहले पंजाबी में सोचना, उसका हिंदी में अनुवाद, और अंत में अंग्रेजी में लिखना। और फिर भी, परीक्षा के लिए समय सिर्फ तीन घंटे ही मिलता था। इस बीच, मेरे पिता अपना उर्दू दैनिक अखबार 'हिंद समाचार' पढ़ते रहे, सेना में बतौर सैनिक गर्ती होकर वे तरक्की पाकर नायब सूबेदार के पद तक पहुंचे थे।

वह लकीर जिसने मुझे हरियाणवी बनाया

राजेश खुल्लर

वर्ष 2025-26 में, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 3.96 लाख रुपये है, जबकि पंजाब की लगभग 2.31 लाख रुपये है। जिस राज्य के बारे में कभी माता जानता था कि वह असफल हो जाएगा, आज उसकी अर्थव्यवस्था उस राज्य से डेढ़ गुना बढ़ी है, जिससे उसने अलग करके बनाया गया था। मैं तीन साल का था, जब भारत के नक्शे पर एक नई, टेढ़ी-मेढ़ी लकीर खींची गई। तीन साल, दो महीने और एक दिन—तीन वैसे ही जैसे बच्चे अपनी उम्र गिनते हैं, यहाँ जानते हुए कि हम बड़े होकर भूल जाते हैं कि हर एक दिन मायने रखता है। और उस दिन ने सच में मायने रखा। 1 नवंबर 1966 को, मेरे माता-पिता ने खुशी-खुशी मुझे बताया कि अब हम हरियाणावी हैं। मैंने इसे ऐसे लिया जैसे कोई बच्चा एक तोहफा पाकर करता है। बहुत बाद में मुझे समझ आया—इसे बनाने में मेरे माता-पिता ने यह करके अपना योगदान दिया। हरियाणा दिवस और पंजाब दिवस एक ही तारीख को आते हैं, जैसे अलग-अलग घरों में पले-बढ़े जुड़वा बच्चे। हर हरियाणावी पंजाब की खबरें ऐसे पढ़ता है जैसे कोई अपने बड़े भाई की खबरें पढ़ रहा हो—जन्मजात स्नेह के साथ, थोड़ी-सी टीस के साथ और मन ही मन महसूस होने वाले थोड़े से गर्व के साथ। हाँ, गंध, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि छोटा भाई (हरियाणा) अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा।

हरियाणा उस समय एक शुष्क और धूल भरा इलाका था—जिसके कमतर माना जाता था, जहाँ न के बराबर उद्योग—धंधे, सड़कें थीं और नहरें भी नहीं थीं, और न ही पैसा था। कहा गया कि कुछ होंगे सालों में यह राज्य असफल होकर रह जाएगा, कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएगा। यह लंकर 1961 की जनगणना आधारित थी। इसी जनगणना के आंकड़ों से यह तय होना था कि पूर्वी पंजाब के मैदानी इलाकों में हर गांव और शहर का भविष्य का पता बसा होगा। पंजाब जनगणना करने वाले अधिकारी आए तो मेरे माता-पिता—जो कि पश्चिमी पंजाब से आकर यहां बसे थे—ने अपनी मातृभाषा में ‘हिंदी’ बताई। यह प्यार से बोला गया झूठ था; एक ऐसे राज्य के लिए दिया गया वोट, जिसका उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था जब हरियाणा बना, तब मैंने अंबाला शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी, जहाँ हर कोई पंजाबी बोलता था। कुछ ही समय में पढ़ाई, हिंदी में किताबें आ गई—एक ऐसी भाषा जिसमें मेरे शिक्षकों और मैंने एक साथ मिलकर सीखा। बाद में, कॉलेज में पढ़ाई की माध्यम अंग्रेजी हो गया। कई सालों तक, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मुझे दिमाग में तीन कदम उठाने पड़ते थे—पहले पंजाबी में सोचना, उसका हिंदी में अनुवाद, और अंत में अंग्रेजी में लिखना और फिर भी, परीक्षा के लिए समय और अंतर तीन घंटे ही मिलता था। इस बीच, मेरे पिता अपना उर्दू दैनिक अखबार ‘हिंद समाचार’ पढ़ते रहते, सेना में बतौर सैनिक भर्ती होकर वे तस्करी पाकर नाबूब सुबेदार के पद तक पहुँचे थे। मेरी माँ अपने दो बेटों की परवरिश के दौरान संस्कृत के ग्रंथों का पढ़ा करती थीं। इस तरह, मैं चार लिपियों और पचास भाषाओं—और उनके साहित्य—के बीच पला-बढ़ा। कोई बहाना न होने के कारण, मैं अपनी माँ के रोज़मर्रा के कामों में हाथ बंटाने लगा और वहीं से मैंने एक बहुत ही कीमती गुण सीखा—कौमलता। हम लोग गरीब थे, और उस समय हरियाणा की गरीब था। मार्च 1977 में, जब मैं 13 साल का था और अभी मैट्रिक भी पास नहीं करी थी, मैंने अपने ही हाई स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में तीन महीने

तक गणित पढ़ाया। इसके लिए मुझे हर महीने 250 रुपये मिलते थे। यह उस पूरी स्थिति का एक छोटा-सा प्रारूप था, जिससे उस समयच्या कूड़ा रख्य गुजर रहा था—यानी, पूरी तरह स्थापित होने के लिए पक्का कोई मेहनत करना, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं था। बाद में, जब मैंने एक गर्ल्स हाई स्कूल और एक कॉलेज में पढ़ाया, तो मुझे समझ आया कि युवाओं के भीतर कुछ बनने की कितनी तीव्र आग होती है। इसके बाद मैं रेलवे में गया, फिर आईपीएस और अंत में हरीशचंद्रा केडर में आईएएस अधिकारी बना। अपनी फील्ड नियुक्तियों के दौरान, 'विकास' मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक ऐसा काम था जिसे मैंने खुद किया या कराया है, शरीर में, गांव-देहात में। यह काम कोसली से शुरू हुआ—जहां मैंने बतौर एसडीएम शुरूआत की थी और रोहतक तक चला, जहां पर एक दशक बाद मैं उप आयुक्त रहा।

हर दिन मुझे दूसरों की मदद करने, लोगों का दुख कम करने, समस्याएँ सुलझाने और वहाँ की स्थानीय बोली सीखने के मौके मिलते थे। राज्य मुख्यालय में काम करते हुए मैंने दूसरा पहलू सीखा : एक राज्य का निर्माण फाइल-दर-फाइल प्रक्रिया से गुजरकर होता है, उन विचारों से जिन्हें ऐसे लोगों ने लिखा और हस्ताक्षर किया होता है, जिनको पर्दे के पीछे रहकर काम करने को तैयार किया जाता है। ऐसा ही एक विचार 1994 में आया—“अपनी बेटी, अपना धन”—जिसके तहत हर नवजात बच्ची के नाम पर सरकार की ओर से एक छोटा बचत निवेश किया जाए। इस विचार की जड़ मेरी इकलौती बहन से जुड़ी थी, जो मुझे पहले पैदा हुई थी, लेकिन कुछ महीनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकी। मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के कार्यक्रम में ‘निदेशक जनसंपर्क’ के रूप में काम करने का मौका मिला। आगे

लालकर, मैं ओम प्रकाश चौटाला, मनाहर लाल और नाबख सिंह सेनी के कार्यालयों में और भी गहराई से जुड़ा रहा। उन वर्षों ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया— 'सीसर को पत्नी' वाला सिद्धांत। सरकार के फैसले न केवल लोगों के लिए अच्छे होने चाहिए, बल्कि वे अच्छे दिखने भी चाहिए। फरीदाबाद और गुरुग्राम (तब गुडगांव) नगर निगमों में बतौर कमिश्नर बिताए चार सालों ने मुझे चीजों को उच्चस्तर पर देखने में और ज़मीनी हकीकत के बीच रहने वाले अंतरों को को बहुत करीब से सिखाया। वर्ष 2025-26 में, हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय लगभग 3.96 लाख रुपये है, जबकि पंजाब को लगभग 2.31 लाख रुपये है। जिस राज्य के बारे में कभी माना जाता था कि वह अफमल हो जाएगा, आज उसकी अव्यवस्था उस राज्य से डेढ़ गुनी बड़ी है, जिससे उसे अलग करने के बनाया गया था। मैं इसी मुद्दे को कानून के साथ नहीं कह रहा हूँ। देश का पैर भरने और उसको रक्षा करने के लिए पंजाब ने अपनी मिट्टी, अपने पानी और एक काले

दरवाक को कोमत चुकाई—जबकि हरियाणा इन सब चीजों से काफी मदद ले रहा। इन पंजाब लड़खड़ाए, तो हरियाणा को उसकी हरदत के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, न कि उसके सामने तुलना करके वाला चार्ट रखना। मुझे राज्य की कमियों को भी अवश्य ही आईना दिखाना होगा। हमारा लिंगानुपात इतना खराब था, कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत के लिए पानीपत को चुना।

सुधार के बावजूद यह अभी भी काफी कम है। हमारा भूलल और हमका खिल्ला खराब हो रही है। पैसा आप पर जरूरी नहीं है। कोई समझदार भी बन जाये। मुझे ज्यादा दिना मुताओं के भीषण को लेकर है। हरियाणा से भारत को अपने भौगोलिक आकार के कहीं ज्यादा खिलाड़ी और सैनिक मिलते हैं। फिर भी, कुछ युवा आपराधिक गिरोहों और नशों को और भटक रहे हैं। यह निराशा पुरानी है। 18 साल को

उम्मीदों में, मैंने फॉरेस्ट रेंजर के पद के लिए लिखित परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन इंटरव्यू में मुझे खारिज कर दिया गया और सलाह दी गई कि मैं 'इंडियन फॉरेस्ट सर्विस' के लिए कोशिश करूं। तीन दशकों तक, हरियाणा के बहुत कम युवाओं को यह भरोसा था कि बिना किसी 'जान-पहचान' या 'सिफारिश' के सरकारी नौकरी मिल सकती है। सुखद है कि 2015 से योग्यता के आधार पर हो रही भर्तियों ने लोगों का यह भरोसा फिर से

बहाल किया है। तो, अपने राज्य के स्थापना दिवस पर मैं उसके लिए क्या कामना करता हूँ? यही कि वह हमेशा कुछ नया करने के लिए बेचैन रहे। वह अपने युवाओं की देखभाल उतनी ही सावधानी से करना सीखे, जैसे हमने पुराना में कुरु ने कुक्षेत्र के खेतों की देखभाल की थी। उन्हें हमें और दिल की थिरता की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम 'प्राण' नामक नए फाउंडेशन के जरिए इस दिशा में काम कर सकेगें, जिसकी शुभ्रुता हम छात्रों के साथ करेंगे। यह फिर से मेरा पहला सबक होगा। शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों मिलकर एक नई भाषा सीखेंगे। 1 नवंबर को, जब हरियाणा अपनी डायमंड जुबली मनाएगा, तब मैं 63 साल, दो महीने और एक दिन का हो जाऊंगा। जगणपना फॉर्म पर मेरे माता-पिता ने मेरी पहचान तय की थी—तब से लेकर आज तक, कक्षा से लेकर चित्र के बड़े बोर्ड तक—मैंने हर दिन खुद ही अपनी यह पहचान बिचनी है। नक्शे पर खींची गई वह लकीर आज घर बन गई है।



विचार

माओवादी आतंक समाप्त: मोदी सरकार में कितना बदला बरत रहा है

कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल

अक्सर कुछ लोग कहते मिल जाते हैं कि भाजपा और मोदी सरकार में क्या ही बदला है ? ये इतना सामायीकरण करने वाला प्रश्न है, जो किसी के गले नहीं उतरता है। कहीं और की बात न कर केवल छत्तीसगढ़ और बस्तर को ही देखें तो हमें पूरी तस्वीर ही अलग दिखाई देती है। भाजपा सरकार ने तय समय पर 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ समेत देश को सशस्त्र माओवादी आतंक से मुक्त कर दिया। बस्तर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहुंचना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये इतिहास की वो लकीर है। जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और समृद्धि की संघर्षमय-प्रतिबद्धता की कहानी कहती है। 2024 में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया था, उस समय लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। विरोध के लिए विरोध करने वाले धड़े, उपहास उड़ा रहे थे। किन्तु जब तय समय सीमा में देश से माओवादी आतंक (नक्सलवाद) समाप्त हो गया तो विरोध करने वाले उपहास का पात्र बनकर रह गए। हालांकि 'अर्बन नक्सली' और उन्हीं के रक्तबीज 'दिमागी नक्सली' आज भी बस्तर में आंखें गड़ाए बैठे हैं। किन्तु वो अब कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पूरा समाज जाग चुका है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 23 अक्टूबर 2026 को बस्तर में राष्ट्रपति का जाना हुआ है। सैकड़ों साल पुरानी 'मुर्गिया दरबार' परंपरा और वहां की कई परंपराओं से राष्ट्रपति का साक्षात्कार होना, हमारी सांस्कृतिक अन्तश्चेतना का प्रतिबिम्ब है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। यह उस संकल्प की परिणति है, जो संकल्प- बस्तर की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर में यही लोकतन्त्र का उदय है, जहां अब लोग निर्भीक होकर जीवन जी रहे हैं। राष्ट्र प्रमुख उनके बीच पहुंच रहे हैं। जबकि इसके पहले 'अर्बन नक्सलियों' की कमांड से संचालित होने वाले सशस्त्र माओवादी- वहां हिंसा, रक्तपात का वीभत्स खेल रचते थे। 'जनतावा' सरकार के नाम पर भारत के लोकतन्त्र और संविधान को चुनौती देते थे। इन्हें किस विचार और पूर्ववर्ती सरकार का घोषित-अघोषित समर्थन प्राप्त था, क्या ये किसी से छिपा है। लेकिन अब नक्सली नेस्तनाबूद हो चुके हैं। जिन माओवादियों ने सरेंडर किया है, उनके पुनर्वास के कार्यक्रम चल रहे हैं। उनको कौशल सम्पन्न बनाया जा रहा है। मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। ये केंद्र की मोदी और राज्य की साय सरकार ने ही कर दिखाया है। आप इनकी और मुद्दों पर आलोचना कर सकते हैं लेकिन माओवादी आतंक को समाप्त करने का जो साहसिक कार्य भाजपा सरकार ने किया है, वो 'न भूतो न भविष्यति' जैसा है।

अब बस्तर में बस्तर पंडुम हो रहा है। बस्तर ओलंपिक हो रहा है। पर्यटन का विस्तार हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़कों का नया जाल बुना जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का बस्तर पहुंचना भी कोई सामान्य बात नहीं है। उनका राष्ट्रपति बनना भी साधारण बात नहीं थी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जनजातीय समाज से आने वाली बेटी 'द्रौपदी मुर्मू' को भाजपा ने सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की आसंदी तक पहुंचाया है। जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने जनजातीय समाज को इसी बेटी के खलिफ़ अपना उम्मीदवार उतारा था। वो किसी भी स्थिति में जनजातीय समाज से आने वाली बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे। भला, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जनजातीय समाज के विरोध में आने से क्या हासिल हुआ? क्या ये कॉर्पोरेटिज़्ड माइंडसेट नहीं था, जो जनजातीय समाज को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहता है? वहीं, गाहे-बगाहे कुछ लोग भारत के लोकतन्त्र को नसीहतें देते रहते हैं। उपनिवेश की मानसिकता के गुलाम आज भी कहते हैं कि '15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत में लोकतन्त्र आया।' ऐसे में उन्हें बस्तर के 'मुरिया दरबार' को जानना चाहिए। जहां सैकड़ों सालों से लोकतन्त्र और जन-संवाद का अद्भुत उदाहरण मिलता है। सैकड़ों गांवों के मांडी, चालकी और प्रतिनिधि 'मुरिया दरबार' में अपनी बातें रखते थे। क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर गहन, चिंतन और विमर्श करने की परंपरा निबंध रूप से जारी है। जहां पूरा समाज एक-दूसरे का पूरक है। भारत के कोने-कोने में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। अंतर केवल इतना है कि भारत ने लोकतन्त्र का झुनझुन नहीं बजाया बल्कि लोकतन्त्र को जीवन में उतारा है। इसे शराब और शैथिल्य में डूबे एससी कमरां में बैठने वाले तथाकथित अकादमिक जल्लाद और गल्पकार (इतिहासकार) नहीं समझ सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो लोग जो हमारे जनजातीय बांधवों को अपने चश्मे से दिखाते हैं। बताते हैं कि 'आदिवासी हिन्दू नहीं हैं।' वो 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे को देखें। हमारा जनजातीय समाज ही बस्तर दशहरे का मुख्य कर्ताधर्ता है। पारंपरिक रीति-रिवाजों, मान्यताओं का जितना कड़ाई से जनजातीय समाज पालन करता है, उसका हम और आप सहस्त्रांश नहीं कर पाते। यही हिन्दुत्व का विराट स्वरूप है।

एक नजर

सारण शिक्षक निर्वाचन में निर्दलीय प्रत्याशी डॉ राहुल राज विजयी



सारण। बिहार विधान परिषद के तीन सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चौदहवें राउंड की मतगणना के बाद निर्दलीय प्रत्याशी डॉ रहलु राज ने अपने निष्कटम प्रतियुद्धी एनटीडी प्रत्याशी आनन्द पुष्कर को हराकर सातवरा जीत दर्ज की है। 14वें राउंड के पश्चात डॉ रहलु राज को कुल 4,965 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतियुद्धी आनन्द पुष्कर को 3,150 मत मिले। निर्धारित कोटा प्राप्त करने के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा डॉ रहलु राज को आधिकारिक रूप से विजयी घोषित कर दिया गया। इस परिणाम के सामने आने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है।

54वें मिथिला विभूति पर्व की तैयारी तेज, एमएलएसएम कॉलेज में होगी तीन दिवसीय समारोह

दरभंगा। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्त्वावधान में 22, 23 एवं 24 नवंबर को आयोजित होने वाले 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। समारोह के सफल आयोजन को लेकर समीपवार के दरेश राम संस्थान के प्रधान कार्यालय परिसर में समीक्षा बैठक हुई। संस्थान के अध्यक्ष सह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शशिनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न समितियों के कार्यो की प्रगति की समीक्षा की गई। संस्थान के महासचिव डॉ. बैदनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि समारोह का उद्देश्य मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत का संरक्षण-संवर्धन करना और नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली परंपराओं से परिचित कराना है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि समारोह में मिथिला पेंटिंग, पारंपरिक कलाकृतियों और मिथिला के पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न स्टॉल के माध्यम से मिथिला की कला, संस्कृति और खानपान की विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। मिथिला की विभूतियों के योगदान को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न दीर्घाओं का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाएगा।

संगीत शिक्षक छात्रों को गायन- वादन में दक्ष बनाएं: डीईओ



सुपौल। कला उत्सव की तैयारी की समीक्षा को लेकर मंगलवार को जिला शिक्षा कार्यालय के एसएसए सभागार में संगीत शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। संगीत शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) संग्राम सिंह ने छात्रों को गायन व वादन में रक्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब जिले के सभी सरकारी स्कूलों में संगीत वाद्य उपलब्ध है। इसका बेहतर उपयोग होना चाहिए। छात्र- छात्राओं को संगीत गायन व वादन की समुचित शिक्षा देना संगीत शिक्षकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास की नींव है। उन्होंने कला उत्सव प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्र- छात्राओं का चयन करने का निर्देश दिया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एसएसए) मणिभूषण कुमार ने संगीत शिक्षकों को पोषक क्षेत्र के स्कूलों में संगीत में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं का समूह तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संगीत गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। मंच पर प्रस्तुति देने या साथ मिलकर अभ्यास करने से बच्चों में टीम वर्क, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास होगा। बैठक में संयोजक नन्दलाल पासवान सहित कई हाईस्कूल के संगीत व ललित कला के शिक्षक मौजूद रहे।

अररिया कॉलेज में नशा मुक्त अभियान के तहत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

अररिया। नशा मुक्त बिहार अभियान के तहत अररिया कॉलेज में मद्यनिषेध विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर डीएम विनोद दूहन सहित जिला स्तरीय पादधिकारी, पुलिस एवं मद्यनिषेध विभाग के प्रतिनिधि, कॉलेज के शिक्षक तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान जिला प्रतिकूल अधिकारी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा न केवल व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशामुक्त बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए इसे जन-आंदोलन का रूप देना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान अररिया कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा नुकड़ नाटक प्रस्तुत कर नशे के दुष्परिणामों को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया। इसके माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश दिया गया।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित करने का बिहार ने किया विरोध, पटना में बनाए रखने का निर्देश



से ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का मुख्यालय पटना में रहा है, लेकिन हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इससे बिहार में बाढ़ प्रबंधन योजनाओं की स्वीकृति और बाढ़ निरोधक कार्यों के समय पर क्रियान्वयन में गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार पहले ही आयोग का मुख्यालय पटना में बनाए रखने का अनुरोध कर चुकी है। आयोग की मूल परिकल्पना के अनुरूप इसका मुख्यालय पटना में ही रहना चाहिए। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी बिहार की मांग का समर्थन किया। बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बाढ़ प्रबंधन योजनाओं की समयबद्ध स्वीकृति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि फ्लड मैनेजमेंट

पिपरा में सात दिनों से लापता अधेड़ का नदी किनारे मिला शव, इलाके में सनसनी

सुपोल। निर्मल के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मली पंचायत के हटवारिया वार्ड नंबर 15 से सात दिनों से लापता अथेड़ का शव मिलने के बाद परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पिपरा थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की गंभीरता पर देखते हुए एफएसएल टीम और प्रभारी सुपर एसडीपीओ गौरव गुप्ता

मृतक की पहचान हठवाौरा सूरजवाडी नंबर 15 निवासी उपेन्द्र सादा उपर्युक्त टीरन के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार, उपेन्द्र सादा को करीब सात दिन पहले गांव के ही किसी व्यक्ति ने पेड़ काटने के लिए बुलाया था। इसके बाद से वह अचानक खो गये थे। काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद परिजनों ने पिंपरा थाना में लिखित सूचना देकर उनके लापता होने की जानकारी दी थी। मंगलवार की सुबह कुछ महिलाएँ आस काटने के लिए नदी किनारे गई थीं। इसी दौरान उन्हें दुर्भाग्यवश महसूस हुई। जब उन्होंने नदी किनारे जाकर देखा तो जलकुंभी के बीच एक शव पड़ा हुआ था। इसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों को दी गई। कुछ ही देर में शव मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान उपेन्द्र

सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी और टीर मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को जलकुंभी से बाहर निकाला गया। कई दिनों तक पानी में रहने के कारण शव की स्थिति खराब हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सुपौल भेज दिया है। घटनास्थल पर आवश्यक जांच की गई और मामले से जुड़े पहलुओं की पड़ताल शुरू कर दी गई है। इधर, मृतक के परिजनों ने उपेन्द्र सादा की हत्या कर शव को नदी किनारे फेंकें जाने की आशंका जताई है। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस थानी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। इस संबंध में प्रभारी सदर एसडीपीओ गौरव गुप्ता ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

सादा के रूप में की। सात दिनों से लापता अडेड का शव मिलने के बाद परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पिपरा थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम और प्रभारी सदर एसडीपीओ गौरव गुप्ता को भी सूचना दी गई।

सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी और टीम मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को जलकुंधी से बाहर निकाला गया। कई दिनों तक पानी में रहने के कारण शव का स्थिति खराब हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सुपौल भेज दिया है। घटनास्थल पर आवश्यक जांच की गई और मामले से जुड़े पहलुओं की पड़ताल शुरू कर दी गई है। इधर, मृतक के परिजनों ने उपेन्द्र सादा को हत्या कर शव को नदी किनारे फेंके जाने की आशंका जताई है। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। इस संबंध में प्रभारी सदर एसडीपीओ गौरव गुप्ता ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर माताये की जांच शुरू कर दी गई है।

**खड़गो के बयान पर भाजपा का विरोध दोहरा मापदंड, नशे का
दलित सम्मान के मुद्दे पर भी जवाब दे पार्टी : अनूपम करने**

सुपौल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के बयान को लेकर भाजपा की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सह जिला कांग्रेस कमिटी, सुपौल के अध्यक्ष अनुपम ने भाजपा पर राजनीतिक विरोधियों के प्रति दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का मुद्दा उठाने वाली भाजपा को पहले अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की भाषा तथा विपक्षी नेताओं के प्रति अपने व्यवहार पर भी जवाब देना चाहिए। दूसरों को राजनीतिक मर्यादा का पाठ पढ़ाने से पहले भाजपा को अपने आचरण पर आत्ममंथन करना चाहिए।

अनुपम ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड्गे के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और दलित समाज से आते हैं। उन्होंने खड्गे की सभा के बाद संबंधित स्थान के कथित शुद्धिकरण की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि जातिगत पहचान पर कठकतें पड़े तो यह समाजिक न्याय का है, मूल्यों और मानवीय गरिमा से जुड़ा गंभीर संसाल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर कई बार संसाल उठे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणियों से लेकर खड्गे के प्रति की गई टिप्पणियों तक। भाजपा को अपने नेताओं और

एंड एंड बैरिएर एरिया त योजनाओं को केंद्र मिलनी आवश्यक है। केंद्र क क दिसंबर के अंत भेज दिए जाएं। इसके और जल शक्ति मंत्रालय ननों को स्वीकृति दें, कार्यों के क्रियान्वयन क महीने का समय मिल दिशा में शीघ्र कार्रवाई में गाद प्रबंधन का विजय कुमार चौधरी ने प्रतिनिधित्व गाद जमा होने से गागारत घट रही है और ते है। गाद के जमाव से जिसके कारण हाल के तनर ग् उच्चतम बिंदु रहा है। उन्होंने आगाह किया कि समय रहते गाद प्रबंधन के प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो नदियों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार ने गाद प्रबंधन को उसके व्यावसायिक उपयोग से जोड़ते हुए देश में पहली बार 'बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026' तैयार की है। उन्होंने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर भी गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग की। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, बिहार के जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, केंद्रीय जल आयोग और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

फारबिसगंज नगर परिषद के कर्मियों ने 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी



अब तक उनका अपेक्षित समाधान नहीं हो सका है। संध ने मांगों के शीघ्र निष्पादन के लिए नगर परिषद प्रशासन और संबंधित विभाग से ठोस पहल करने की अपील की। बैठक में कर्मचारी संघों के साथ नियमित मासिक वाता आयोजित करने, कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने तथा विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा पूर्व में हुई आठ दिवसीय हड़ताल की अवधि का बकाया वेतन भुगतान करने और आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग भी शामिल है। कर्मचारियों ने सेवा अभिलेखों का नियमित संधारण, समय पर वेतन भुगतान, भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा की राशि जमा करने, अनुकंपा एवं लंबित मामलों का निष्प्राणी में अंशदान पेशा साथ ही बकाया पेंशन सेवाविवृत कर्मचारियों के निपटारा और एक ही समय से कार्यरत क स्थानांतरण करने की मांग बैठक में नगर परि कर्मियों की स्थानीय हुई। कर्मचारियों ने ब के बोर्ड की बैठक में है के मानदेय में प्रतिवर्ष प्रस्ताव पारित किया अब तक संबंधित काम

जमा करान, अनुकंपा के आधार पर लिखित मामलों का निष्पादन तथा राष्ट्रीय प्रणाली में अंशदान बढ़ाने की मांग रखने के साथ ही बकाया पेंशन, वेतनांतर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिखित निपटारा और एक ही पद पर तीन वर्षों के समय से कार्यरत कर्मियों का स्थानांतरण करने की मांग भी उठाई गई।

बैठक में नगर परिषद के दैनिक कर्मियों की स्थानीय समस्याओं पर हुई। कर्मचारियों ने बताया कि 2 नवम्बर को बोर्ड की बैठक में दैनिक एवं संचालक के मानदेय में प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की प्रस्ताव पारित किया गया था। इससे अब तक संबंधित कर्मियों को इसका

और चिताजनक बात यह है कि पुल के सहित दक्षिणी हिस्से के पिलर में गहरी दरारें आ चुकी हैं। बाढ़ के दिनों में एक तरफ से गंगा का बैकवाटर और दूसरी ओर से झारखंड के पहाड़ी इलाकों से आने वाले तेज बहाव की दोहरी मार ने इस पुल को समय से पहले जर्जर कर दिया। वर्तमान में कंक्रीट हटाकर लोहे के हिस्सों को दुरुस्त करने का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है, और मौके पर किसी जिम्मेदार इंजीनियर की गैर-मौजूदगी के कारण काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मुख्य मार्ग के बंद हो जाने से कहलागांव, पीरपैती, विक्रमशिला और साहिबगंज (झारखंड) की लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। यात्री और आम नागरिकों को भागलपुर मुख्यालय जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटकर खरनाका बायपास रास्तों से जाना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे संत जोसफ, डीएवी, और केंद्रगिय विद्यालय जैसे बड़े स्कूलों के लगभग 10 हजार बच्चों की पढ़ाई बाधित है। बच्चों को दोनों तरफ गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं और जान जोखिम में डालकर पैदल पुल पार करना पड़ता है, जिससे रोज 2 घंटे अतिरिक्त बर्बाद हो रहे हैं।

जमा कराने, अनुकंपा के आधार पर लॉबीटिंग मामलों का निष्पादन तथा राष्ट्रीय प्रणाली में अंशदान बढ़ाने की मांग राखी। सचिव ही बकाया पेंशन, वेतनांतर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लॉबीटिंग निपटारा और एक ही पद पर तीन वर्षों के समय से कार्यरत कर्मियों का निष्पादन स्थानान्तरण करने की मांग भी उठाई। बैठक में नगर परिषद के दैनिकीय कर्मियों की स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई। कर्मचारियों ने बताया कि 2 नवंबर को बोर्ड की बैठक में दैनिक एवं सविनियोजित कर्मियों के मांगों पर प्रतिक्रिया के मानदंडों पर प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत प्रस्ताव पारित किया गया था। इससे अब तक संबंधित कर्मियों को इसका

था है। संघ ने पिछले चार वर्षों के बकाया कर का भुगतान अविलंब करने की मांग की। साथ ही, आठ दर्जन से अधिक वैधिक कर्मचारियों को पिछले आठ वर्षों से भौतिक निधि का लाभ नहीं मिलने को इसे गंभीर समस्या बताते हुए बड़े बत लाभ उपलब्ध कराने की मांग की। संघ अध्यक्ष सूरज कुमार सोनू ने नगर परिषद प्रशासन को अधिकप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दोहरी रातें अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व कुछ कर्मचारियों की सेवा का तकाफ़ा खोली गई, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में कर्मचारी इससे वंचित हैं। उनके अनुसार, सेवा का तकाफ़ा से वंचित कर्मचारियों में अधिकांश वृद्ध व महिला सदस्य के हैं, जिसको लेकर कर्मियों में नाराजगी है।

वाब देना जुड़े उस 5 भाजपा सी मुख सी खड़गे र रही है। के सम्मान पर प्रतिक्रिया र्णर्ष नेतृत्व ने कहा, हंकरा से वालों का में कुर्सी की ताकत संबोधित में कांग्रेस कच्छप ने को लेकर प लगाते दहन कर

रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. विश्वनाथ सराफ ने कहा कि राजनीतिक आलोचना और व्यक्तिगत अपमान के बीच अंतर समझना जरूरी है। सुपौल प्रखंड प्रभारी शाहिद खान ने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। भाजपा को इन सवालों पर जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता अब केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि बुनियादी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा करती है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी ने कहा कि सत्ता के बल पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश सफल नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के आंबेडकर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांकेतिक पुतला दहन कर विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के विरोध प्रदर्शनों से कांग्रेस की आवाज कमजोर नहीं होगी।

फिटनेस के लिए निकालने की अधिवेशन कार्यक्रम से जुड़े राजकीय कॉन्ग्रेस हॉल में युवाओं को न दियायी। उन्होंने भविष्य को ध्यान रहने की अपील विद्यार्थियों सहनी, उच्च शि और उम्मुख्य संबोधन को भ समान बिहार अधीक भार शारीरिक और म विशेष ध्यान देन को गंभीरता से नशे की लत व्य बबंद कर सक्ते दूर रहकर अपने

अपनी की। 27 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलने वाले नशामुक्त बिहार अभियान के तहत जिले में विभिन्न चरणों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। पहले चरण में 27 से 31 अक्टूबर तक नगरीय क्षेत्रों में 'नगर की प्रतिज्ञा' अभियान चलाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जायेगा। दूसरे चरण में एक से सात नवंबर तक 'गांव का संकल्प' अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे। तीसरे चरण में आठ से 16 नवंबर तक पर्व के दौरान परिवारों के बीच जागरूकता फैलायी जायेगी। वहीं, चौथे चरण में 17 से 25 नवंबर तक 'युवा जोश' अभियान के तहत युवाओं को नशामुक्तिके प्रति जागरूक किया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कालेज परिसर में विद्यार्थियों के साथ पौधरोपण किया और उनसे संवाद कर नशे से दूर रहने का संदेश दिया। नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार वाहन को भी खाना किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों और विद्यार्थियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। उत्पाद एवं मद्य निषेध अधीक्षक विपिन कुमार ने अतिथियों का पौधा और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी बालेंदु नारायण पांडेय, प्रभारी जनसंपर्क पदाधिकारी उदेंद्र कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सत्या सिंह, नेटवर्क इंजीनियर हिमांशु प्रकाश, कालेज के प्राचार्य डॉ. सूर्यकांत सिंह, शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता गणेश दत्त पाठक उपस्थित रहे। मंच संचालन उदय सिंह ने किया।

एक नजर

एचएस चट्टा मेमोरियल एमटी–400 चैंपियंस कप अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में विभिन्न आयु वर्गों में हुए मुकाबले



मुरादाबाद। मुरादाबाद में आयोजित हो रहे एचएस चट्टा मेमोरियल एमटी–400 चैंपियंस कप अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट के पांचवे दिन मंगलवार को नागराज, मेहर प्रकाश, ओपी दीक्षित, डेनियल, अशोक, सुरेंद्र मोहन शर्मा, एजेएस चटवाल, आर गंगाधरन, पुनीत गुप्ता और जयप्रकाश समेत खिलाड़ियों ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। कांठ रोड स्थित ब्रास सिटी जिमखाना में आयोजित प्रतियोगिता में मंगलवार को 45, 55, 60, 65 और 70 आयु वर्ग के मुकाबले खेले गए। 70 आयु वर्ग में चंडीगढ़ के सुरेंद्र मोहन शर्मा ने नोएडा के अरविंद को 6–1, 6–2 से हराया। अमेरिका के एजेएस चटवाल ने बेंगलुरु के सुदेश को 6–2, 6–2 से पराजित किया। जोधपुर के आर गंगाधरन ने लखनऊ के सुधीर कुमार को 6–1, 6–0 से शिकस्त दी। 60 आयु वर्ग में पुनीत गुप्ता ने दिल्ली के विपिन कुमार सिन्हा को 6–1, 6–1 से हराया। मैसूर के नागराज ने दिल्ली के प्रेम सिंह रोहिला को 6–0, 6–1 से मात दी। हैदराबाद के मेहर प्रकाश ने गुवाहाटी के भरत को 6–0, 6–2 से पराजित किया। जयपुर के ओपी दीक्षित ने मुरादाबाद के अनिल निगम को 6–1, 6–2 से हराकर जीत दर्ज की। 45 आयु वर्ग में जर्मनी के डेनियल ने दिल्ली के आनंद को कड़े मुकाबले में 3–6, 6–3, 10–5 से शिकस्त दी। वहीं 65 आयु वर्ग में कोलकाता के अशोक ने मुरादाबाद के अजीत भारद्वाज को 6–1, 6–2 से हराया। इसके साथ ही 55 आयु वर्ग में जयप्रकाश ने तुलेश्वर को 6–2, 6–4 से पराजित किया। विश्व टेनिस संघ के तत्वावधान में चट्टा गुप की ओर से सरदार गुरजीत सिंह चड्ढा के नेतृत्व में आयोजित प्रतियोगिता 29 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान मुरादाबाद क्लब के कोच ऋग्भ अभ्रवाल, टेनिस खिलाड़ी ओजस, वंश, ओजस भारद्वाज, एआईटीए टेनिस खिलाड़ी डॉ. अनुराग अग्रवाल, चट्टा गुप के अध्यक्ष गुरजीत सिंह चट्टा, मुरादाबाद टेनिस एसोसिएशन के सचिव अवनीश रस्तोगी, राहुल आदि मौजूद रहे।

स्पर्धा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ओलंपियाड में आरएसडी एकेडमी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने जीते आठ पदक



मुरादाबाद। सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ में आयोजित ‘स्पर्धा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2026’ में आरएसडी एकेडमी पब्लिक स्कूल, मुरादाबाद के जूडो खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट कौशल, दृढ़ संकल्प और कड़े परिश्रम के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर और देश का नाम रोशन किया है। आरएसडी के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 6 कांस्य पदक जीते। जुड़ो कोच मयंक करश्यप ने बताया कि कई दिनों तक चली इस बेहद रोमांचक और कठिन प्रतियोगिता में दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देते हुए आरएसडी एकेडमी की चैंपियन टीम ने कुल 8 पदक अपने नाम किए। जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल हैं। मयंक करश्यप ने आगे बताया कि ख्याति सिंह ने स्वर्ण पदक, गुनी चौधरी ने रजत पदक, हिमांशु सैनी, अभिराज ठाकुर, मान्या शर्मा, रानी यादव, शुभांग सिंह और नमन कुमार कांस्य पदक जीता। आरएसडी एकेडमी की खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि पर आरएसडी एकेडमी के निदेशक डॉ. विनोद कुमार, डॉ. जो कुमार, डॉ गौरव कुमार, डॉ. गरिमा शर्मा, डॉ. अजय शर्मा , प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा ने सभी विजेताओं और कोच मयंक करश्यप को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर मिली इस बड़ी कामयाबी से पूरे विद्यालय और मुरादाबाद जिले में हर्ष का माहौल है।

एसबीआई लाइफ की ‘अनोखे हीरे’ फिल्म में दिखा भारतीय पैरा खिलाड़ियों का जज्बा

मुंबई। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय पैरा खिलाड़ियों के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने वाले जज्बे को समर्पित अपनी नई फिल्म ‘अनोखे हीरे’ पेश की है। फिल्म का उद्देश्य उन मानवीय मूल्यों को रेखांकित करना है, जो लोगों को चुनौतियों का सामना करने, अपने सपनों को साकार करने और अपनों से किए वादों को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिल्म की कहानी अक्ष नाम के एक छोटे बच्चे की जिज्ञासा से शुरू होती है, जो अपने आसपास की चीजों में असाधारण चमक वाले हीरे तलाशता है। उसकी यह खोज उसे एक पैरा खेल प्रशिक्षण केंद्र तक ले जाती है। वहां खिलाड़ियों के अनुशासन, निरंतर अभ्यास और मजबूत इच्छाशक्ति को देखकर उसे एहसास होता है कि अखिली हीरे वे लोग हैं, जिनकी चमक उनके व्यक्तित्व और इरादों में दिखाई देती है। फिल्म का संदेश है कि असली चमक बाहरी रूप में नहीं, बल्कि नेक इरादों, आत्मविश्वास और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहने में होती है। यह भी दिखाया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा अक्सर खुद से किए गए वादों और अपनों के प्रति जिम्मेदारियों से मिलती है। फिल्म के लॉन्च पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष फर्न बांड, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और सीएसआर प्रमुख रवींद्र शर्मा ने कहा कि हर आकांक्षा के साथ एक वादा जुड़ा होता है। यह वादा खुद से भी हो सकता है और उन लोगों से भी, जो हमारी जिंदगी में सबसे अधिक मायने रखते हैं।

अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक से भारत ने जीती सीरीज, न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया

वेलिंगटन,एजेंसी। अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार को पांच मैचों की टी–20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराकर सीरीज में 3–0 की अजेय बढ़त बना ली। अभिषेक ने महज 35 गेंदों में शतक पूरा किया और 38 गेंदों पर 113 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 11 छक्के और 9 चौके लगाए। भारत ने 199 रनों का लक्ष्य केवल 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने जैकब डफी के पहले ओवर में 26 रन बटोरे। दूसरे ओवर में 17 और तीसरे ओवर में 21 रन बने। इस तरह भारत ने महज तीन ओवर में बिना विकेट खोए 64 रन बना लिए। भारतीय बल्लेबाजों का आक्रामक अंदाज पावरप्ले में भी जारी रहा। टीम ने चौथे ओवर में 20, पांचवें में 16 और छठे ओवर में 18 रन बनाए। भारत ने छह ओवर में बिना किसी नुकसान के 118 रन बना डाले। अभिषेक ने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

मैथ्यू फिशर ने आठवें ओवर में वैभव सूर्यवंशी को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। वैभव ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें चार छक्के और चार चौके शामिल रहे। हालांकि, अभिषेक ने इसी ओवर में दो छक्के और एक चौका जड़कर भारतीय टीम को 156 रन तक पहुंचा दिया। अभिषेक ने काइल जैमीसन के खिलाफ 10वें ओवर में महज 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इसके बाद भी उनका



आक्रामक खेल जारी रहा। जैमीसन ने अंततः उन्हें 113 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। अभिषेक ने 38 गेंदों की अपनी पारी में 11 छक्के और नौ चौके लगाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और संजु सैमसन के विकेट गिरने से भारत की रफ्तार कुछ धीमी हुई लेकिन टीम ने 40 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की ओर से जैमीसन ने दो विकेट लिए, जबकि फिशर और मिचेल सैंटरन को एक-एक विकेट मिला। हालांकि, न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज 12 रन प्रति ओवर से कम की दर से रन खर्च नहीं कर सका। इससे पहले न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल की 89 रन की शानदार पारी की मदद से तीन विकेट पर 198 रन बनाए। मिचेल ने 52 गेंदों पर 89 रन बनाए, जिसमें आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला। बेवन जैकब्स ने 23 गेंदों पर 39 रन का योगदान दिया। दोनों ने चौथे विकेट के

लिए 75 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को अर्शदीप सिंह ने शुरुआती झटका दिया। उन्होंने टिम सीफर्ट को दो रन पर आउट किया। इसके बाद मिचेल और फिन एलन ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 86 रन जोड़े। एलन ने 25 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें पांच छक्के शामिल रहे। उन्हें नितीशा कुमार रेड्डी ने आउट किया। ग्लेन फिलिप्स अपने 100वें टी–20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 17 रन ही बना सके। उन्हें अक्षर पटेल ने 12वें ओवर में पवेलियन भेजा। इसके बाद मिचेल और जैकब्स ने पारी को आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड की टीम एक समय 100 रनों पर दो विकेट खोकर मजबूत स्थिति में थी लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाया और मेजबान टीम को 200 रन के पार नहीं जाने दिया।

हरमनप्रीत और दीप्ति को आईसीसी रैंकिंग में फायदा, स्मृति से छिना नंबर एक का ताज

दुबई। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में शतक जड़ने वाली पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को आईसीसी की ताजा महिला एकदिवसीय रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। वहीं, भारतीय कप्तान और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान गंवा दिया है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट्द फिर से दुनिया की नंबर वन एकदिवसीय बल्लेबाज बन गई हैं।

हरमनप्रीत दो स्थान की छलांग लगाकर एकदिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में आठवें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं, दीप्ति शर्मा ने चार स्थान का सुधार करते हुए 23वां स्थान हासिल किया है। एकदिवसीय ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी दीप्ति को फायदा हुआ है। वह दो स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में भी उन्होंने एक स्थान का सुधार करते हुए आठवां स्थान हासिल किया है। भारतीय खिलाड़ियों में क्रांति गौड़ ने भी दो स्थान की छलांग लगाई है और वह एकदिवसीय गेंदबाजों की रैंकिंग में 25वें स्थान पर पहुंच गई हैं। युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल को सात स्थान का फायदा हुआ है। वह बल्लेबाजों की रैंकिंग में 21वें स्थान

पर पहुंचकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर काबिज हो गई हैं। एकदिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट्द ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल के दो मुकाबलों में स्मृति मंधाना ने 32 रन और शून्य का स्कोर बनाया था। इसके कारण उन्हें रैंकिंग अंक गंवाने पड़े और वह शीर्ष स्थान से नीचे खिसक गई। जिम्बाब्वे की तीन बल्लेबाजों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। मोडेस्टर मुपाचिकवा पांच स्थान ऊपर चढ़कर 39वें, चिपो मुगेरी-तिरिपानो चार स्थान के सुधार के साथ 47वें और बिलव्ड बीजा 16 स्थान की छलांग लगाकर 56वें स्थान पर पहुंच गई हैं। टी–20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने सुधार किया है। शेफाली वर्मा एक स्थान ऊपर चढ़कर बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि स्मृति मंधाना एक स्थान के फायदे के साथ चौथे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हाल में खेली हुई टी–20 सीरीज के बाद दोनों टीमों की खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की एग्ले गार्डनर बल्लेबाजों की रैंकिंग में नौ स्थान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग : शाहरुख और आशीष पूर्ति ने संस्कारधानी स्ट्राइकर्स को दिलाई पहली जीत, राजधानी रॉयल्स को 4–2 से हराया

रायपुर। संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने मंगलवार रात ललित उपाध्याय की राजधानी रॉयल्स को 4–2 से हराकर छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में अपनी पहली जीत दर्ज की। हमशेर की कप्तानी वाली स्ट्राइकर्स टीम शानदार फॉर्म में दिखी। मैच में आशीष तानी पूर्ति और शाहरुख ने 2–2 गोल किए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ चंदन कुमार, शारदा गुप के चेयरमैन (वित्त) योगेंद्र शुक्ला, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक आदर्श श्रीवास्तव, गोयल गुप के मार्केटिंग हेड चंद्रशेखर और छत्तीसगढ़ प्रदेश सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के महासचिव ओपी शर्मा भी इस मैच को देखने स्टेडियम पहुंचे थे।

संस्कारधानी स्ट्राइकर्स और राजधानी रायल्स दोनों के लिए यह मुकाबला बहुत अहम था। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह उनके पास आखिरी मौका था, क्योंकि इससे पहले दोनों में से किसी को भी जीत नहीं मिली थी। शुरुआत में खिलाड़ियों पर दबाव साफ दिख रहा था। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने संभलकर शुरुआत की। दोनों ही टीमों को अटैक करने या सर्कल के अंदर पहुंचने में मुश्किल हुई और उनका पूरा ध्यान गेंद पर अपना कब्जा बनाए रखने पर था। फिर भी, स्ट्राइकर्स के लिए आशीष ने एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके खाता खोला। काफी संघर्ष के बाद, हाफ-टाइम ब्रेक बजने से ठीक पहले, रॉयल्स ने भी मैच में वापसी की। रोशन ने रिवर्स हिट



के जरिए गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। यह खेल का एक बेहतरीन नजारा था, जिसमें उन्होंने सर्कल के अंदर कुछ खिलाड़ियों को छकाया, बाईं ओर थोड़ी जगह बनाई और फिर एक शानदार शॉट लगाकर स्कोर बराबर कर दिया।

राजधानी रायल्स का डिफेंस काफी हद तक अच्छा था, लेकिन शाहरुख को खुला छोड़ देने की एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। उन्होंने सर्कल के ठीक अंदर से एक ‘रिवर्स फ्लिक’ के जरिए गोल कर दिया। उस पल के बाद संस्कारधानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशीष ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टूर्नामेंट में अपने कुल गोलों की संख्या 9 तक पहुंचा दी। तीसरे क्वार्टर के खत्म होने में जब एक मिनट बचा था, तब शाहरुख ने एक बार

फिर गोल किया। उन्हें दाईं ओर से पोस्ट के ठीक सामने एक बेहतरीन पास मिला था, जिसे उन्होंने गोल में बदल दिया। अब सवाल सिर्फ अपनी बढ़त को और बढ़ाने का था। हालाँकि, राजधानी के लिए ललित ने भी गोल किया।

एक पेनल्टी कॉर्नर के रिवाउंड पर उन्होंने गेंद को नेट के अंदर पहुंचा दिया। आशीष को ‘स्ट्राइकर ऑफ द मैच’ और शाहरुख को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला। आज के पहले ही मैच में लीग के सेमीफाइनलिस्ट मिल गए, जब सुरेंद्र सिंह की ‘न्यायधानी नाइट्स’ और एस.वी. सुनील की ‘चक्रधर चैंपियंस’ के बीच मुकाबला 4–4 से ड्रा रहा। पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बने रहने के कारण नाइट्स ने आगे का सफर तय किया।

राजगीर में भारत–न्यूजीलैंड रग्बी सीरीज संपन्न, खेल कूटनीति को मिला बढ़ावा

राजगीर। बिहार के राजगीर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक अंडर–20 रग्बी सीरीज मंगलवार को संपन्न हो गई। दोनों देशों के खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस सीरीज ने खेल कूटनीति, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और युवा खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय अनुभव को बढ़ावा देने में खेल की भूमिका को रेखांकित किया।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड्गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेलों के माध्यम से वैश्विक सहयोग मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खेल देशों के बीच आपसी समझ, मित्रता और सांस्कृतिक संवाद बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। भारत–न्यूजीलैंड अंडर–20 रग्बी सीरीज दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे खेल संबंधों को नई मजबूती देने का उदाहरण है। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्य की खेल एवं युवा मामलों की मंत्री श्रेयसी सिंह, भारत में न्यूजीलैंड के कार्यवाहक उच्चायुक्त मैट आयर्स, बिहार रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष संजय मयूख और रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड की अंडर–20 पुरुष

एवं महिला टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के तहत संयुक्त प्रशिक्षण सत्र, सांस्कृतिक गतिविधियां और रग्बी सेवन्स के चार मुकाबले आयोजित किए गए। इनमें दो मिश्रित टीमों के मुकाबले भी शामिल थे, जिनमें दोनों देशों के खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते नजर आए। न्यूजीलैंड के दल में माओरी समुदाय के 24 युवा खिलाड़ी शामिल थे। पुरुष टीम ‘टामा तोआ’ और महिला टीम ‘हिने तोआ’ के खिलाड़ियों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और अपने देश की परंपराओं व अनुभवों को भारतीय खिलाड़ियों के साथ साझा करने का अवसर मिला। बिहार की खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राजगीर में इस आयोजन की मेजबानी करना राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और युवा खिलाड़ियों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा कि यह सीरीज केवल खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान, टीम भावना और मित्रता जैसे मूल्यों को भी बढ़ावा देती है। उनके अनुसार, मिश्रित टीमों के मुकाबलों ने दोनों देशों के खिलाड़ियों को साथ खेलने और एक–दूसरे से सीखने का विशेष अवसर दिया।

अदाणी अहमदाबाद मैराथन में चार पूर्व सैनिक दौड़कर देंगे जवानों के हौसले का संदेश



रेफरल अस्पताल और पुणे के आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में उपचार के बाद वह दोबारा चलने में सक्षम हुए। हालांकि, चोट से उबरने के बाद उनके सामने एक और चुनौती खड़ी हुई। उपचार के बाद बड़े वजन ने उनके लिए नई मुश्किलें पैदा कर दीं। उन्होंने सख्त खानपान और अनुशासित दिनचर्या के जरिए अपने शरीर को दोबारा स्वस्थ बनाया। आज अशोक कुमार समाजसेवी होने के साथ वॉर वारंडेड फाउंडेशन के स्वयंसेवक और नियमित मैराथन धावक भी हैं। उन्होंने अपने संघर्ष को याद करते हुए कहा, ‘चोट लगने के बाद मुझे लगा था कि सबसे कठिन काम दोबारा चलना सीखना होगा। लेकिन वास्तव में इसके बाद की परिस्थितियां

ज्यादा चुनौतीपूर्ण थीं। वजन बढ़ना, मानसिक रूप से आने वाली कठिनाइयां और सबसे बड़ा सवाल कि अब मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये सभी चीजें मेरे लिए चुनौती थीं। उन्होंने आगे कहा, ‘फाउंडेशन ने मुझे एक दिशा दी। जब मैंने उन दूसरे घायल सैनिकों के अनुभव सुने, जो इसी तरह की परिस्थितियों से गुजर चुके थे, तो मुझे समझ आया कि दिव्यांगता को भी क्षमता में बदला जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैराथन में शामिल हर व्यक्ति अपने घर एक संदेश लेकर जाए कि इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अपने सैनिकों के लिए अदाणी अहमदाबाद मैराथन में दौड़ने पर मुझे बहुत गर्व है।’

आईएसएसओ की राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में 56 स्कूलों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

अहमदाबाद। इंटरनेशनल स्कूल्स स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (आईएसएसओ) की आठवीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026–27 रविवार को अहमदाबाद में संपन्न हो गई। विजयी भारत स्पोर्ट्स अकादमी (संस्कारधाम) में आयोजित इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में देशभर के 56 स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 14 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम और 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक और बालिका शामिल हैं। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली तमन्ना ने 2021 में पोलैंड में आयोजित युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को समर्पण, अनुशासन और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तमन्ना देशवाल ने कहा, ‘इतनी बड़ी संख्या में युवा तीरंदाजों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते और अपनी प्रतिभा एवं दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते देkhना बहुत अच्छा है। इस तरह की चैंपियनशिप युवा खिलाड़ियों में आत्मविश्वास, अनुशासन और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जरूरी एकाग्रता विकसित करने में मदद करती हैं। मैं सभी

प्रतिभागियों को लगातार सीखते रहने, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। आईएसएसओ की निदेशक आकांक्षा थापक ने कहा, ‘आईएसएसओ में हम ऐसे व्यवस्थित प्रतिस्पर्धात्मक मंच तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमता पहचानने और उसे विकसित करने में मदद करें। इस चैंपियनशिप में 56 स्कूलों की भागीदारी तीरंदाजी के प्रति बढ़ती रुचि और कम उम्र से ही खेल प्रतिभाओं को निखारने के महत्व को दर्शाती है। इस चैंपियनशिप को सफल बनाने में सहयोग के लिए हम अपने आयोजन साझेदारों का आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय राउंड में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों में द श्रीराम अकादमी के आदित्य निम्मागुड़ा और बालिकाओं में विजडम वेल्थ इंटरनेशनल स्कूल की नानी बेट्सुसी एम ने खिताब जीते। 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों में इंडस अल्ट्रम इंटरनेशनल स्कूल के नियान पोरवाल विजेता बने, जबकि बालिकाओं में बेलगावी स्थित इंडस अल्ट्रम इंटरनेशनल स्कूल की आस्था श्रीकांत तोतागी ने पहला स्थान हासिल किया। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों में संजय घोड़ावत इंटरनेशनल स्कूल के वीर शितलकुमार कदम ने खिताब जीता। बालिकाओं में 21वें स्कूल की हरिया भक्ति गिनिज ने पहला स्थान हासिल किया। रिकर्व राउंड के 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों में इला प्रीत स्कूल के पी. तरुण प्रणीथ और बालिकाओं में जेएस ग्लोबल स्कूल की तिया वेंकटेश ने स्वर्ण पदक जीते।

एक नजर

नई पीढ़ी को नशे की लत का शिकार होने से नहीं रोका गया, तो बर्बाद हो जाएगा बिहार : मुख्यमंत्री



पटना।बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को ‘ नशा मुक्त बिहार अभियान-2026 ’ का शुभारंभ करते हुए राज्य में सूखे नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचना जरूरी है, अन्यथा बिहार का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले एक महीने तक राज्यभर में विशेष नशामुक्ति अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों, जीविका दीदियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘ विकसित भारत ’ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ‘ नशामुक्त भारत ’ के संकल्प का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार भी इसी दिशा में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएगी। सम्राट चौधरी ने वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से लागू शराबबंदी का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्व की चिंता किए बिना लिया गया यह निर्णय महत्वपूर्ण था। उन्होंने इसे सफल पहल बताते हुए कहा कि क़रीब दस वर्षों से राज्य में शराबबंदी लागू है, लेकिन अब स्मैक, चरस और अन्य सूखे नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन पर अंकुश लगाना बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों की जब्त की आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 2024 में राज्य में 282 किलोग्राम चरस जब्त की गई थी, जो 2025 में बढ़कर 400 किलोग्राम हो गई। इसी अवधि में हेरोइन की जब्त 42 किलोग्राम से बढ़कर 62.65 किलोग्राम पहुंच गई, जबकि अफीम की जब्त 10 किलोग्राम से बढ़कर 77 किलोग्राम हो गई। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है। इसके लिए राज्य के आठ जिलों को विशेष रूप से चिह्नित किया गया है। मुख्यमंत्री ने पटना, समस्तीपुर, वैशाली और आरा का उल्लेख करते हुए इन क्षेत्रों में सूखे नशे की समस्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। नशामुक्ति अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें विद्यार्थियों, जीविका दीदियों और ब्रह्माकुमारी संस्था की बहनों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्था पहले से देशभर में नशामुक्ति के लिए काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वस्थ और उज्ज्वल बिहार का निर्माण तभी संभव है, जब समाज के सभी वर्ग मिलकर युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास करें। उन्होंने अभियान को गांव–गांव और आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

लिकटेंस्टाइन के प्रिंस की भारत यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई गति मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली। लिकटेंस्टाइन के प्रिंस एलोइस की भारत यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा से सरकारों और कारोबारों को संघर्ष बढ़ाने के अवसर मिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रिंस की मंगलवार को हुई वार्ता में तकनीक, नवाचार और कौशल विकास में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर प्रिंस एलोइस 25 से 28 अक्टूबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन में आज सुबह उनका औपचारिक स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में भोज दिया। यह उनकी भारत की पांचवीं यात्रा है। उनके साथ उनकी पत्नी राजकुमारी सोफी, एक उच्चस्तरीय अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है। इसमें लिकटेंस्टीन के विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री, साथ ही लिकटेंस्टीन स्थित कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के शिक्षकों ने राजनीतिक हस्तक्षेप और ‘बाहरी लोगों’ द्वारा परिसर (कैंपस) को अस्थिर करने की कोशिशों की निंदा की

सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया

(जेएमआई) के शिक्षकों ने विश्वविद्यालय परिसर को अस्थिर करने, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालने और राजनीतिक हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की है। शिक्षकों ने राजनीतिक तत्वों द्वारा छात्रों के चल रहे विरोध-प्रदर्शनों को और भड़काने तथा एक बड़ा संकट पैदा करने के लगातार प्रयासों पर गहरी नाराजगी जताई है। यह चिंता कल संकाय डीन, विभागाध्यक्षों, केंद्रों के निदेशकों और विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों (जिनमें परीक्षा नियंत्रक, मुख्य प्रॉक्टर, हॉस्टल प्रोवोस्ट और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं) की एक बैठक में उलाई गई। यह बैठक परिसर की स्थिति का जायजा लेने, आँनलाइन कक्षाओं की अवधि की समीक्षा करने और विरोध कर रहे छात्रों की मांगों पर विचार–विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी।

शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू की एक फेसबुक पोस्ट पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया और कड़ी आलोचना की। जस्टिस काटजू ने जेएमआई के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को जारी एक आदेश की आलोचना की थी। यह आदेश भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को सौंप गए मांग–पत्र को स्वीकार करने के संबंध में था। इस आदेश के तहत यह तय किया गया था कि: 1) छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे; 2) विरोध–प्रदर्शन के



दौरान छात्रों के निलंबन और उन्हें जारी किए गए ‘कारण बताओ’ (शो–काँज) नोटिस वापस लिए जाएंगे; और 3) विरोध–प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। जहां जस्टिस काटजू ने छात्रों के संघ बनाने के अधिकार के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(८) का हवाला दिया, वहीं शिक्षकों ने उनके इस दावे पर सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। शिक्षकों का कहना है कि यह बात जेएमआई प्रशासन द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को जारी किए गए उक्त आदेश की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। शिक्षकों ने बताया कि मौजूदा प्रशासन ने जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ (जेएमआईस) को बहाल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2006 में हिंसक झड़पों और शिक्षकों (जिनमें तत्कालीन

कुलपति भी शामिल थे) पर हमलों की लगातार घटनाओं के बाद इस छात्र संघ को भंग कर दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 20 वर्षों में यह पहला प्रशासन है जिसने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं, जबकि इतने सालों से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। शिक्षकों ने इस बात पर भी जोर दिया कि 21 अक्टूबर को एक ‘संविधान समीक्षा समिति’ (draft constitution committee) का गठन किया गया था। इस समिति को अदालत 1आदेशों, लिंगदोह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों, और विश्वविद्यालय के लागू नियमों व कानूनों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के आंतरिक मामले को राजनीतिकरण करने की राजनीतिक दलों की कोशिशों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और

इमरान मसूद के अनधिकृत रूप से परिसर में घुसने के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन को 25 अक्टूबर को सन्नद्धर्जन करानी पड़ी। शिक्षकों के अनुसार, इमरान प्रतापगढ़ी 21 अक्टूबर को गेट नंबर 4 का ताला तोड़कर परिसर में घुसे थे, जबकि इमरान मसूद 23 अक्टूबर को गफूर नगर के पास एक सीढ़ी की मदद से बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर आए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को भी परिसर आते समय हिरासत में लिए जाने का जिक्र किया, और बताया कि अन्य राजनीतिक नेता भी प्रशासन को पहले से कोई सूचना दिए बिना परिसर में आए थे। शिक्षकों ने इस बात पर गहरा दुःख जताया कि चल रहे विरोध–प्रदर्शन के बीच, ‘विश्वविद्यालय के बाहर के लोगों’ ने 24 अक्टूबर से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विभागों की इमारत पर कब्जा कर लिया है और वहां ताला लगा दिया है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति के कारण विश्वविद्यालय को उस तारीख से लेकर दिवाली की छुट्टियों तक पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना पड़ा है, और आगे की स्थिति की समीक्षा के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों और उच्च–स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल ‘पूर्व छात्रों, जामिया के संस्थापक परिवारों के सदस्यों, कलाकारों, पत्रकारों, वकीलों और अन्य नागरिकों के एक समूह’ द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में बुलाई गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय और उसके पीछे के इरादों पर भी सवाल उठाए।

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ के चर्चित नीला ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल दोषियों की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। साथ ही अपील पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दोषसिद्ध साहित्य शुक्ल और मुस्कान रस्तोगी की अपील पर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अपील स्वीकार की जाती है। अपर शासकीय अधिवक्ता को अपील की पूर्व सूचना प्राप्त है। ट्रायल कोर्ट द्वारा मयूल्दंड की पुष्टि के लिए संदर्भ भी भेजा गया है और सत्र अदालत के रिकॉर्ड इस संदर्भ के साथ भेज दिए गए हैं। कार्यालय किसी भी स्थिति में 16 नवंबर तक पेपर बुक तैयार करे। मामले को सुनवाई के लिए 30 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाए।

साहिल शुक्ल और मुस्कान रस्तोगी ने अपील में मेरठ की सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को चुनौती दी है। मेरठ की सत्र अदालत ने गत 14 अक्टूबर को दोनों को फांसी और 50–50 हजार रुपये जमाने की सजा सुनाई थी। अपील में

30 सितंबर के दोषसिद्ध आदेश और 14 अक्टूबर के सजा के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

यह है मामला यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि दोनों ने सौरभ की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसे एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और ट्रायल कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले की अवैध और मनमाना बताते हुए इसे पूरी तरह

निरस्त करने और भारतीय न्याय संहिता के तहत सभी आरोपों से बरी करने की मांग की है। अपीलार्थियों तर्क है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और सत्र अदालत स्थापित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी कर अनुमानों और अटकलों पर पहुंची। यह भी कहा गया है कि हथियार, सीमेंट और ड्रम की खरीद और सबूत मिटाने के बयानों में गंभीर विरोधाभास हैं तथा इनकी खरीदारियों की पुष्टि के लिए कोई वैध रसीद या सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की गई।

एसआईआर को लेकर झारखंड विस का विशेष सत्र 25–26 नवंबर को, कैबिनेट ने दी मंजूरी

रांची,एजेंसी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आहुत होगा। यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट में कहा गया है कि विधानसभा का विशेष सत्र शीतकालीन सत्र के दौरान आहुत किया जाएगा। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडे़ल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कैबिनेट ने कुल 62 प्रस्तावों पर सहमति दी। कैबिनेट में झारखंड मेडिको सिटी के लिए संबद्ध आधारभूत संरचना के निर्माण लिए 2 अरब 84 करोड़ 17 लाख 24 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर परिसर में 500 शय्या वाले अस्पताल के भवन निर्माण की योजना के लिए पांच अरब 45 करोड़ 38 लाख 33 हजार रुपये की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी। कैबिनेट ने चॉडिल जलाशय से जल लिफ्ट कर सरायकेला–खरसावा जिलान्तर्गत नीमडीह एवं कुकड़ प्रखंड में भूमिगत पाईपलाईन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर नीमडीह–कुकड़ मेगालिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 06 अरब 07 करोड़ 03 तीन लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान के लिए राज्य के 263 प्रखंडों में 7890 चापाकल लगाने के लिए 96 करोड़ 54 लाख 70 हजार रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के आदिवासी बहुल गांवों के अविद्युतीकृत टोलों और घरों के विद्युतीकृत करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए–जेजीयूए) योजना के लिए प्राक्कलित राशि 184.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- कैबिनेट की बैठक में राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए मनोनयन के आधार पर झारखंड टूल रूम रांची, दुमका और रामगढ़ का चयन करने की स्वीकृति दी गई। इन शिक्षण संस्थानों के सहयोग से यहां के छात्रों को इंटरशिप करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा–8 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए स्ट्रॉचूट फोर हेल्थ् केयर मैनेजमेंट एंड मेंटी वेलबींग–2026’ की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट विषयों के अध्ययन, अनुसंधान एवं इस पर तकनीकी परामर्श निमित्त विषय विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने के लिए झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्य प्रणाली नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गई।
- राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए विभागीय आदेश पर झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेपीएचसीएल), रांची की ओर से चर्चनित परामर्शी मेसर्स एनरेंटर् एंड यंग एम्पलपी को लंबित भुगतान के लिए राशि एक करोड़ 17 लाख 52 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- हजारीबाग जिलान्तर्गत लोटिया जलाशय योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहरों के लार्निंग कार्य के लिए 3217.06 लाख रुपये (बत्तीस करोड़ सत्रह लाख छः हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से विभिन्न तिथियों को 11 रिट याचिकाओं में पारित न्यायादेशों का अक्षरशः एवं वास्तविक भावना के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशनादि लाभ प्रदान किए जाने संबंधी पूर्व में निर्गत कुल 11 (ग्यारह) विभागीय संकल्पों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- विदेश यात्रा के लिए सरकारी सेवकों को अनुमति देने स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान को सोसायटी निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए झारखण्ड



राजकोषीय अध्ययन संस्थान का उप–विधि के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

- राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति, सेवा शर्तों में एकरूपता एवं एसीपी और एमएसीपी संबंधी मामलों के निराकरण के लिए पूर्व गठित समितियों को विलोपित करते हुए नई उच्च स्तरीय समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली–2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2026–27 और 2027–28 में राज्य योजना के तहत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना अन्तर्गत झारखण्ड मिल्क फेडरेशन (जेएमएफ) के माध्यम से गोड्डा में 50 एमटीपीडी का नया पशु आहार कारखाना की स्थापना के लिए पांच अरब एक करोड़ 49 लाख रुपये की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026–27 में रुपये 30 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई।
- नावाई–आरआईडीएफ–ट्रेंच अंतर्गत स्वीकृत झारखंड जलछाजन योजना (जेजेवाई) के कुल 28 जलछाजन परियोजनाओं के लिए बची शेष राशि 58 करोड़ को राज्य संसाधन मद से स्वीकृत करते हुए परियाजना को 31 मार्च, 2027 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- विकसित भारत–जी राम जी योजना अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों को देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त राशि एक अरब 28 करोड़ 31 लाख रुपये की स्वीकृति से संबंधित संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई। राज्य के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से जन वितरण प्रणाली

दुकानदारों को मुक्त करने को लेकर झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली–2011 में नए नियम जोड़ने की स्वीकृति दी गई।

- दशरथ मंडल एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश एवं कंटेप्ट केस में दशरथ मंडल सहित अन्य में पारित फैसले पर वादी दशरथ मंडल, सेवानिवृत्त कोपरक्षक, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा सहित 16 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से पेंशन की स्वीकृति दी गई।
- मधुराक्षी उप–बेसिन के जल संसाधनों के बंटवारे और मयूराक्षी उप–बेसिन में मसानजोर बांध एवं दामोदर उप–बेसिन में तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण के तौर–तरीकों से संबंधित समझौते के प्रस्ताव को औपचारिक रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के बीच निष्पादित करने वाले एकरारनामा पर सहमति के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह जिलान्तर्गत ‘बड़कीटांड (एसएच पर) जबरदाहा–निमायीटांड–शंकरडीह– मरजुगुण्डी पथ (कुल लंबाई–7.783 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण पर 40.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह अन्तर्गत मदहालो (एनएच–19) से अलकडीहा पीडब्ल्यूक डी पथ भाया खेतको पथ (7.800 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य 37.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- पथ प्रमण्डल, गिरिडीह अन्तर्गत पतालडीह–देवरी–गांवा सतगांवा पथ (एमडीआर–84) (42.40 किमी) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य के लिए रुपये 37.06 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- लातेहार जिला के चंदवा अंचल के मौजा–चकला के विभिन्न प्लॉटों में 147.05 एकड़ गैरमजरूआ आम/खास भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए मेसर्स हिंडाल्कोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए शुल्क के साथ लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 131 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- 400/200 केवी ग्रिड सब स्टेशन, चाईबासा (पीजी) में

मेरठ का ब्लू ड्रम मर्डर केस : फांसी के खिलाफ दोषियों की अपील विचारार्थ स्वीकार, 30 नवंबर को होगी सुनवाई



30 सितंबर के दोषसिद्ध आदेश और 14 अक्टूबर के सजा के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

यह है मामला यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि दोनों ने सौरभ की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसे एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और ट्रायल कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले की अवैध और मनमाना बताते हुए इसे पूरी तरह

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा(यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से

प्रकाशित किया।सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।(संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)

